खंड ९ संख्या-५

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-२—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित ।)

मंगलवार, तिथि ११ जून, १९७४

विषय सूची ।

	पृष्ठ
डाक्टरों के हड़ताल पर जाने की चर्चा	१
छात्र आन्दोलन से सम्बन्धित चर्चा	१-२
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :	
(क) श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विधान-सभा का विघटन	३-४
(ख) राज्य के सरकारी डाक्टरों का इस्तीफा	४
सभा मेज पर रखे गये कागजात	
(क) लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन	५
(ख) बिहार राज्य टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन का सप्तम प्रतिवेदन	५-६
(ग) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग का प्रतिवेदन	६
राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद (समाप्त)	६-६८
श्री फुलेना राय, स० वि० स० की गिरफ्तारी की सूचना	६८
निवेदन के सम्बन्ध में सूचना	६८
दैनिक निबन्ध	६९-७१

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

है उस पर विचार-विमर्श के लिये सदस्यों को अवसर मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिलता है तो इस तरह का प्रतिवेदन रखना उचित नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन में जो बातें हैं वह तो सदन में आ जाती हैं लेकिन जो उसके संबंध में हमलोगों को कहना है वह नहीं आती है।

उपाध्यक्ष—आपके साथ हम बिल्कुल सहमत हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि बिजनेस ऐडवाईजरी कमिटी में इस बात को रखें।

श्री जनार्दन तिवारी—खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पर भी एक प्रतिवेदन है और श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष हैं। उसकी प्रगति क्या है ? उसमें क्या गोलमाल हुआ है, इस पर विचार-विमर्श होना चाहिये।

उपाध्यक्ष—अगर बिजनेस ऐडवाईजरी कमिटी से समय इसके लिये मिलेगा तो विचार होगा। हम बिजनेस ऐडवाईजरी कमिटी में रख देंगे और समय मिलेगा तो उस रिपोर्ट पर जरूर वाद-विवाद होगा।

(ग) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग का प्रतिवेदन

*श्री चन्द्रशेखर सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रगति प्रतिवेदन १९७२-७३ की प्रति सभा की मेज पर रखता हूँ।

(सभी प्रतिवेदन सभा की मेज पर रखे गये)

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद

*श्री रामरतन राम--उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मैं छोटानागपुर की समस्याओं के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण में छोटानागपुर में जो हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनके उत्थान के लिये कोई विशेष बातें नहीं कही गयी हैं।

विशेषकर मैं उन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि हमलोग जानते हैं कि हमारा प्रान्त कृषि प्रधान है। कृषि उत्पादन के लिये सभी

साधन भी उपलब्ध है। लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे यहाँ अन्न की बहुत बड़ी कमी है और यह एक जटिल समस्या बन गयी है। अगर हम अपनी समस्याओं को सही ढंग से समाधान करना चाहते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजलीकरण की ओर ध्यान देना होगा, यह बात ठीक है कि बिजलीकरण का कुछ काम नोर्थ बिहार में हुआ है लेकिन छोटानागपुर में कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई काम नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहा नदी है, नाले हैं, अगर सरकार चाहे तो लिफ्ट ऐरिगेशन के जरिये वहां का उत्पादन बढ़ा सकती है।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक उद्योग का प्रश्न है, हमारा क्षेत्र उद्योग में अपना स्थान रखता है, इसका स्थान न केवल प्रान्त में ही है बल्कि देश में भी है। मैं देखता हूँ कि इसकी ओर भारत सरकार का तो कुछ ध्यान है किन्तु बिहार सरकार का ध्यान कुछ नहीं है। भारत सरकार तो वहां के उद्योगों को प्रगतिशील बनाने के लिये प्रयत्नशील है। हमारे यहां बोकारो स्टील है। हमारे यहां सभी चीजों के खान भी भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी प्रगति के लिये प्रान्तीय स्तर से जो काम होना चाहिये नहीं हो रहा है। हमारे छोटानागपुर में लघु उद्योग के लिये भी कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी गयी है। यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है कि वन हमारे लिये एक बहुत बड़ी सम्पति है किन्तु सिर्फ श्री करमचन्द भगत ही एक ऐसे वन मंत्री बने थे जिनका इस ओर ध्यान था और वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि छोटानागपुर के लिये जब तक वन सम्पदा की तरक्की नहीं होगी, छोटानागपुर की तरक्की नहीं होगी। इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके विपरित जो भी आजतक वन मंत्री हुए उनका इस ओर कोई ध्यान न रहा और न है। आज वहां का जंगल कट रहा है लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। जहाँ तक जंगल को बचाने का सवाल है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। अगर जंगल नही रहेगा तो वर्षा भी नहीं होगी, आज हमारे आदिवासी भाई की क्या हालत है, आप जाकर देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो जंगल समाप्त कर दिया गया है उसकी वजह से वहां के लोगों को जीवन-यापन में बड़ी कठिनाई हो रही है।

दूसरी बात मैं उस क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। उस क्षेत्र की ओर मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र सिली की जमीन काफी अच्छी है। लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती है कि वहाँ की जमीन की सिचाई की जा सके, वहाँ की जमीन को पटवन मिल सके। हमारे इलाके में काफी नदियाँ हैं जिसमें सालो भर पानी रहता है। वहां बहुत से नाले भी हैं जिससे कि सिचाई का काम लिया जा सकता है लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया है। उस इलाके की नदियों को यदि बांध दिया जाय तो उससे पटवन का काम लिया जा सकता है, लेकिन आजतक सरकार ने नहीं किया। उस इलाके की नदियां इतनी अच्छी हैं कि उससे लिफ्ट इरिगेशन का काम भी लिया जा सकता है और वहां की जमीन का पटवन भी किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इस काम को नहीं किया।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि हरिजन और आदिवासी क्षेत्र में बिजली दी जायगी लेकिन आजतक उस इलाके में बिजली नहीं पहुंचायी गयी है।

जहाँतक रोड की बात है, उस क्षेत्र में हाईवे निर्माण का काम गत १५ साल से चल रहा है और उस पर लाखों रुपये खर्च किये गये, लेकिन वह रोड अभी तक बन नहीं सकी है। वह रोड गोला से चांडील तक जमशेदपुर को छूती हुई जाती है, लेकिन वह सड़क लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं बन सकी है। वहां के लोग अनाज को कौन कहे रुपया दो रुपये की दवा के लिये भी शहर तक नहीं जा सकते हैं। क्योंकि उस इलाके में काफी नदियां हैं, और वहाँ के लोग दवा के बिना मर जाते हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार इस बात की जांच कराये कि लाखों लाख रुपया खर्च होने के बाद भी वह सड़क अभी तक क्यों नहीं बन पायी है। मैं दो और सड़कों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आर० ई० ओ० के अन्दर जो रोड निर्माण का काम लिया गया है, उसमें एक रोड बुंडू से सिली तक जाती है जो २४ मील की सड़क है और दूसरी सड़क बुंडू से सोलनातू तक जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस रोड के निर्माण कार्य में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस इलाके के रोड की हालत काफी दयनीय है और उसमें कोई प्रगति नहीं हो पायी है।

मैं सरकार का ध्यान हरिजन आदिवासी के कल्याण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हरिजन आदिवासी की जो समस्यायें हैं, जहां तक उनको नौकरी में स्थान मिलने का प्रश्न है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हरिजन आदिवासी कल्याण समिति, जो विधान सभा द्वारा गठित की गयी है, उसमें जो विभाग से पदाधिकारी आते हैं उनका कहना है कि किसी भी विभाग में हरिजन आदिवासी का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। जो हरिजन आदिवासी को रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये वह नहीं मिला है। साथ ही जब हरिजन आदिवासी के रिजर्वेशन का सवाल इस समिति के माध्यम से विभाग के सामने रखा गया तो विभाग के पदाधिकारी यह सोचते हैं कि हम इनको इस तरह का रिप्रेजेन्टेशन दें तो क्यों दें। मैं तो कहता हूँ कि संविधान में इस तरह का प्रोवीजन है कि अमुक अनुपात में हरिजन आदिवासियों के लिये नौकरी में स्थान रिजर्व है। लेकिन जब पदाधिकारी समिति के सामने आते हैं तो कहते हैं कि हमको हरिजन आदिवासी मिलते नहीं हैं। मैं तो कहूँगा कि हमारे यहां हजारों की तायदाद में हरिजन आदिवासी आते हैं नौकरी के लिये, वे बी० ए०, एम० ए० पास होते हैं और कहते हैं कि किरानी के पद की क्या बात, यदि उनको चपरासी की भी नौकरी दी जाय तो वे लेने को तैयार हैं। जो बहाल करनेवाले पदाधिकारी हैं, जो बहाल करनेवाले व्यक्ति हैं, वे बहाना बना करके कह देते हैं कि हरिजन आदिवासी कैन्डीडेट मिलते ही नहीं हैं। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है। एक तरफ हमलोग कहते हैं कि एम० ए०, बी० ए० पास करके लोग बैठे हैं, वे कहते हैं कि किरानी की बात छोड़ दीजिए, हमलोग चपरासी की जगह पर भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पदाधिकारिगण कहते हैं कि हरिजन, आदिवासी उम्मीदवार मिलते ही नहीं है। आप इस बात की जांच कर देखें। हमने समिति में पदाधिकारियों को बुलाकर पूछा है, वे जवाब नहीं दे पाते हैं, चुप लगा जाते हैं। वे केवल कहते हैं कि हमलोग प्रयास कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि मैं अधिक नहीं चाहता, जो हरिजनों के लिए १४ परसेन्ट और आदिवासियों के लिए ९ परसेन्ट रिजर्वेशन है उतना देने में तो ईमानदारी करें, लेकिन वे तो बराबर कहते हैं कि हरिजन, आदिवासी उम्मीदवार मिलते ही नहीं हैं। इसके बाद देखा जाय, जो हरिजन, आदिवासी नौकरी में हैं, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। बराबर हरिजन, आदिवासी उम्मीदवार आकर कहते हैं कि हमको नौकरी तो दिखा दिया लेकिन वे लोग हमको नौकरी नहीं करने देते हैं। पूछने से मालूम

होता है कि उनके साथ इस तरह का मेन्टल फोजिकल टोरचर होता है कि वह काम नहीं कर सके। आप कल्याणकारी राज की बात करते हैं और दूसरी ओर यहां ऐसी सोसाइटी है, ऐसे लोग हैं जो हरिजनों, आदिवासियों को टोरचर करते हैं, वे उनके साथ सहृदयता से नहीं देखते हैं। मेरा अनुभव है कि हरिजनों, आदिवासियों के साथ ये लोग सहृदयता से पेश नहीं आते। आज पुलिस विभाग की बात करते हैं, पुलिस वाले अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन वहां भी इनके साथ इसी तरह का व्यवहार होता है। सिपाही छुआछूत को दूर करने के लिए है, लेकिन जब सिपाही के मेस में खाना बनता है तो वहां हरिजनों, आदिवासियों को कहा जाता है, तुम अन्दर मत जाओ, उनको वहां नहीं जाने दिया जाता है। इस तरह आज के युग में भी मुझे ऐसा महसूस करना पड़ रहा है कि जो रक्षक हैं, वही भक्षक हैं, पुलिस-वाले भी अपने मेस के अन्दर हरिजन, आदिवासी को नहीं जाने देते हैं। जब मैंने इसकी शिकायत आई० जी० से की तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लीन रहने दें। मुझे पता नहीं लगता कि यह कौन सा डिसिप्लीन है। केरल की बात है, वहां के बारे में यहां बोलना उचित नहीं है, लेकिन वहां ऐसी भावना है कि जिस गली से उच्च जाति के लोग चलें उस गली में भी हरिजन आदिवासी नहीं जा सकते। इस तरह का समाज है कि आपके दिल दिमाग से यह भावना निकलनेवाला नहीं है। आप हरिजन, आदिवासी के साथ सहृदयता के साथ बात करने की बात सोच भी नहीं सकते और कहते हैं कि हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है, हमको बढ़ाने की बात करते हैं।

वर्तमान समस्या है, विधान सभा भंग करो, इस संबंध में छोटानागपुर के लोग जो वहां के असली रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि विधान सभा भंग मत करो, विधान सभा भंग हो जायगा तो हमारी समस्या का समाधान करने वाला कौन होगा, हमारी बातों को सुननेवाला कौन होगा ? वे डिमोन्सट्रेशन लेकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि विधान सभा भंग नहीं होनी चाहिए, विधान सभा भंग करने वाले प्रतिक्रियावादी लोग हैं, वे जनतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। वहां के ९५ प्रतिशत लोग, पुराने आदिवासी कहते हैं, वे ऐसे प्रतिक्रियावादी लोग जो विधान सभा को भंग करने की बात करते हैं, लोकतंत्र को भंग करने की बात करते हैं, उनका वे विरोध करते हैं।

अब मैं छात्र आन्दोलन की जो बातें चल रही हैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। इस आन्दोलन के आड़ में जनतत्र को समाप्त करने के लिये सारी साजिशें चल

रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई चाहता है कि प्रान्त से देश से भ्रष्टाचार मिटे अन्याय मिटे तो मैं समझता हूँ कि इस सदन के कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो एक स्वर से साथ नहीं दे। लेकिन इसके आड़ में विधान सभा को भंग करने की जो बात चल रही है उसे हम बुद्धिजीवी कतई नहीं मान सकते हैं। हमारे क्षेत्र के तो वे गरीब पिछड़ी हरिजन आदिवासी लोग तो एक स्वर से यह नहीं चाहते हैं कि विधान सभा भंग हो और हमारा एक मात्र प्रतिनिधि विधान सभा से बैठ जाय। विधान सभा भंग होने से जो भ्रष्टाचार, अन्याय व्याप्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वह कतई दूर नहीं हो सकती। दूसरी ओर उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों का समय एक साल का मांगा गया है और स्कूल-कॉलेज छोड़ने की मांग की गयी है इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर कुठाराघात हुआ है। १९४२ में गांधी ने विद्यार्थियों का एक साल का समय मांगा था, लेकिन वह आजादी की लड़ाई थी और यह देश बनाने की बात है। यहाँ कोई लड़ाई नही है। हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग तो एक स्वर से इसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि स्कूल-कालेज बन्द रहें, और हमारे बच्चे पढ़ने-लिखने से वंचित रहें।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि अगर यह सदन बिहार राज्य का सही रूप में आइना होता तो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं होता, वल्कि शोक का प्रस्ताव होता। आज इस राज्यपाल के अभिभाषण के चलते बिहार में कितने नौजवानों को कुर्बानी करनी पड़ी। कितने नादान मासूम बच्चे की जानें गयीं। गोलियां खानी पड़ी। ये सारी स्थिति इस राज्यपाल के अभिभाषण के चलते हुई। इस राज्यपाल के अभिभाषण के चलते ही आज नौबत आयी है कि विधान सभा भंग करो। इसलिये इस राज्यपाल के अभिभाषण को हम धन्यवाद का प्रस्ताव कतई नहीं मान सकते बल्कि शोक का प्रस्ताव मानना श्रेयस्कर होगा। अगर यह सदन बिहार की जनता का सही रूप में आईना है तो इस राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को रद्द करे, चाहे इसके लिये गफूर साहब को हटना पड़े। यह बात दूसरी है कि इसके पहले भी एक नयी और बेहाई सरकार बन चुकी है, लेकिन यह सरकार भी रद्दी और बेहाई है। मैं गफूर साहब को कोई रद्दी आदमी नहीं मानता हूँ, उनसे भी रद्दी लोग आगे रह चुके हैं, लेकिन यह समय का दोष है।

यह महाकाल की माया है। यह कांग्रेस की जो सरकार है उससे दूसरी कांग्रेस की सरकार जो आयेगी वह और भी बहुत बुरी होगी क्योंकि वह अधोगति की ओर जा रही है। आप जानते हैं कि जब कोई गिरने लगता है तो और भी गहराई में गिरता चला जाता है। पांडेजी की सरकार से गफूर साहब की सरकार खराब है और इनके बाद आपके यहां जो लोग सपना देखते हैं कि हम मुख्य मंत्री बनेंगे और हमारी सरकार अच्छी होगी तो उनकी सरकार और भी बुरी होगी। समय का यही तकाजा है। दारोगा बाबू की सरकार भले ही कुछ अच्छी रही हो चूंकि वह समय कुछ अच्छा था। आज इस सदन में कुछ लोग कह रहे हैं कि विधान-सभा को तोड़ो और कुछ लोग कह रहे हैं कि विधान-सभा को रखो और पांच साल के लिये रखो तो ये दोनों जनतंत्र के विरोधी हैं। जो कहते हैं कि विधान-सभा को पांच साल के लिये रखो, वे जनतंत्र के विरोधी हैं और जो कहते हैं कि इस्तीफा दो, वे भी जनतंत्र के विरोधी हैं। (ताली की आवाज) मैं इसलिये खड़ा नहीं हूँ कि आप हमारी बातों पर ताली पीटिये। मैं इसलिये खड़ा हूँ कि अपने दिल के फफोले को निकाल दूं। वास्तव में जिस दिन यह आन्दोलन शुरू हुआ था, उसी दिन हमारी गिरफ्तारी हुई थी। मेरी गिरफ्तारी हुई बम फेंकने के इल्जाम में और आग लगाने के इल्जाम में। यह मेरी पहली गिरफ्तारी नहीं थी। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इसके पहले भी मेरी गिरफ्तारी हुई थी। कृष्ण वल्लभ बाबू की सरकार ने मुझे गिरफतार किया था। उस समय की सरकार के खिलाफ में था। इस सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे कि उस समय की सरकार ने मुझे बम फेंकने तथा आग लगाने के इल्जाम में गिरफतार नहीं किया था बल्कि डी० आई० आर० में मुझे गिरफ्तार किया था। क्या यह सरकार उस सरकार से भी गिर गयी कि इसने मुझे बम फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। क्या माननीय सदस्यों को यह विश्वास है कि भोला प्रसाद सिंह बम फेंकेगा और आग लगायेगा ? अगर मुझे बम फेंकना रहता तो सेक्रेटेरियट में बम नहीं फेंकता बल्कि मुख्य मंत्री पर बम फेंकता। मेरा विश्वास बम में नहीं है और न गोली में है।

*श्री विद्याकर कवि—माननीय सदस्य ने गंभीर बात की ओर संकेत किया है। वह बम फेंक सकते हैं और वह मुख्य मंत्री पर। इसलिये जरा निगरानी रखी जाय उनपर। (हंसी)

उपाध्यक्ष—लेकिन जिस दिन चलायेंगे उस दिन देखा जायगा ! (हंसी)

श्री भोला प्रसाद सिंह - जिस रोज मुझे विश्वास हो जायगा कि देश की राजनीति का फैसला बम से होगा तो यहां मैं बैठा नहीं रहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अहिंसा में विश्वास है, हिंसा में नहीं। यह गांधी जी का मार्ग है। गांधी जी का बताया हुआ दूसरा रास्ता वोट का है। लोग कहते हैं कि वोट के रास्ते में विधान सभा का विघटन का नारा, इस्तीफा देने का नारा से जनतंत्र को कहां खतरा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि १८ मार्च को भी यह नारा था कि विधान सभा को भंग करो और इस्तीफा दो।

उपाध्यक्ष—यह नारा नहीं था, लेकिन यह नारा उस वक्त था कि गुजरात की जीत हमारी है अब बिहार की बारी है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—लेकिन कुंए में भांग पड़ा हुआ है। जब पहाड़ पर आप चढ़ते हैं और पहाड़ के एक टीले पर चढ़ते हैं तो पहाड़ का दूसरा टीला दिखाई पड़ता है और जब दूसरे टीले पर चढ़ जाते हैं तो तीसरा टीला दिखाई पड़ता है और उसी तरह पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी दिखाई पड़ती है। हम बुरे हो सकते हैं, हमारे दोस्त बुरे हो सकते हैं, श्री विद्याकर कवि बुरे हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष—आप इन्हीं का नाम क्यों लेते हैं ?

श्री भोला प्रसाद सिंह—हम दोनों साथी रहे हुए हैं और एक ही सदन से आये हुए हैं। विधान सभा भंग करो की बात है तो मैं साफ शब्दों में विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हम बुरे हो सकते हैं और हमसे बुरे हमारे दोस्त हो सकते हैं और हमलोगों को हटना चाहिये। लेकिन विधान सभा वोट की कोख से पैदा हुई है और जब विधान सभा भंग करो का नारा उठेगा तो इसके बाद दूसरा नारा हो जायेगा कि उस कोख को खत्म करो जिस कोख से विधान सभा की उत्पति हुई है। वह कोई इंगलैंड से नहीं आई है। और जब विधान सभा भंग हो जायेगी तो उसके बाद यह लाजिमी होगा कि जिस कोख ने पैदा किया है उसपर अब चोट करो। आज चोट विधान सभा पर है और कल वोट पर चोट होगा। जयप्रकाश बाबू का मैं आदर करता हूँ। अभी विधान सभा भंग करो का नारा है, आंदोलनकारियों का और जब "विधान सभा तोड़ो" नारा सफल

होगा, तब उसके बाद सीधे चोट होगा कोख पर और इसका कोख वोट है और वोट पर सीधे चोट होगा।

मैं आपसे सीधे कहना चाहता हूँ कि वोट को हम नहीं खोना चाहते हैं, हम वोट को त्यागना नहीं चाहते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान के ६० प्रतिशत लोगों के कल्याण का अगर कोई मार्ग है तो वह वोट है।

आज यह प्रश्न उठ खड़ा हो गया है कि विधान सभा बचे कैसे। विधान सभा जनता का आईना है। यह आपके बैठने का स्थान नहीं है। जब जनता की तस्वीर यहाँ नहीं आयगी तो जनता विधान सभा को तोड़ेगी। आज आप देख रहे हैं कि गया में इतने लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सदन में चर्चा तक नहीं हुई। आज दाम आसमान छू रहा है। जिस चीज की कीमत एक रुपया है १५ दिनों के बाद उसकी कीमत ठीक दुगुनी हो जाती है। आज सूबे में बेकारी, भ्रष्टाचार और महंगी की आग लगी हुई है—आप चिल्लाते हैं कि विधान सभा बचाओ लेकिन आपके चिल्लाने से विधान सभा नहीं बचेगी यह तब बचेगी जब जनता की तस्वीर विधान सभा रुपी आईना में आयेगी। मैं चाहता हूँ कि यह सदन गूंगा नहीं बने कारण यह सदन रक्षा की जगह है, लेकिन १८ तारीख को जब विधान सभा भंग करने के लिए आन्दोलन हुआ तो आप रक्षा कहाँ से करते, भाग खड़े हुए। बौद्ध धर्म इस देश के कल्याण के लिए आया था और "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" इसका उद्देश्य था लेकिन जब यह गिरने लगा तब यह उद्देश्य बदल गया "मद मांसच मीनच, मुद्रामैथुनमेवच ऐते पंचमकारा: तुमोक्षदायी युगे-युगे।" "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" की जगह पर मद, मांस, मछली, मदिरा और मैथुन आ गया, नतीजा यह हुआ कि शंकराचार्य का उदय हुआ और बौद्ध धर्म गिरता गया। उसी तरह गांधी, अम्बेडकर, जवाहर लाल नेहरू ने वोट के रास्ते को पैदा किया, लेकिन आप लोग उक्त ढंग से इसको बदल दिया। जिस तरह बौद्ध धर्म को गिरते समय शंकराचार्य का उदय हुआ उसी तरह इन्दिरा ब्रिगेड के जरिये आप गिर रहे हैं।

वोट का राज्य न्याय का राज्य है, वोट का राज्य बलिदान का होता है। वोट का राज्य भोग का नहीं होता है, चक्कलस का नहीं होता है, लेकिन आप चक्कलस बना दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज परिस्थिति है वह परिस्थिति कोई मामूली परिस्थिति नहीं है। सदन में बहुत-से हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, दीप बाबू हैं, कमलदेव बाबू हैं, रामनारायण मंडल

जी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि १९५२ में जब जीतकर आए थे तो उस समय एम० एल० ए० को लोग प्रतिष्ठा की नजर से देखते थे, श्रद्धा की नजर से देखते थे, और उनके प्रति आदर का भाव रहता था। लेकिन उसके बाद से कैसी परिस्थिति बदलती गयी है यह बात अब छिपी हुई नहीं है। आज जयप्रकाश बाबू कह रहे हैं कि एम० एल० ए० लोग विधान-सभा की कमाई पर पलते हैं।

उपाध्यक्ष—एम० एल० ए० लोग डिवैलुड हो गये हैं ?

श्री भोला प्रसाद सिंह—जरूर हो गए हैं।

श्री चतुरानन मिश्र—अपने पार्टी के एम० एल० ए० के बारे में कह रहे हैं तो ठीक है और उनको कहने का अधिकार हो सकता है, लेकिन सभी के बारे में नहीं कह सकते हैं।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जो एम० एल० ए० लोग जीतकर आते थे, वे श्रद्धा के पात्र माने जाते थे उन्हें लोग झुककर प्रणाम करते थे। अगर ये लोग समझते हैं कि डिवैलुयेशन नहीं हुआ है तो अपने को आप भुला रहे हैं। महोदय, १९५५ में भी गोली चली थी, लेकिन इस तरह का घेरा नहीं घेरा गया था।

सन् १९५५ में गोली चली थी तो क्या उस समय इस तरह का पुलिस का घेरा था ? नहीं। हम जानते हैं कि आज एक सदस्य सदन से बाहर निकलने के बाद गिरफ्तार हो जायेंगे। मेरा आपसे यह आग्रह होगा कि आप कम-से-कम हमको १५ मिनट समय और दें।

उपाध्यक्ष—अन्तराल के बाद आपको १० मिनट समय और दिया जायेगा।

(अन्तराल)

श्री श्याम नारायण पांडे—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक या डेढ़ घण्टे से मेम्बर के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, इसको आप देखें। एक डी० आई० जी० यहाँ आये। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह का पुलिस का व्यवहार क्यों हो रहा है।

उपाध्यक्ष—क्या सदन के अन्दर पुलिस आई ?

श्री श्याम नारायण पांडे—जी हां।

उपाध्यक्ष—मैं इसको देखूंगा।

श्री श्याम नारायण पांडे—मैं चाहता हूं कि इन्साफ हो। इस तरह का व्यवहार मेम्बरों की प्रतिष्ठा हनन का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष—हम पता लगा लेंगे कि क्या बात है।

श्री श्याम नारायण पांडे—इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि डी० आई० जी० हाउस के अन्दर आवें। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि डी० आई० जी० हाउस के अन्दर आये हैं।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह जो मौजूदा आन्दोलन है और आन्दोलन करने वालों की जो मंशा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं नतीजे को देखता हूं। आज इस आन्दोलन का नतीजा आप देख लीजिए, विरोधी बेंच टूट चुका है, विरोधी बेंच खाली है, विरोधी पार्टी टूट चुकी है। जो इस सदन में विरोध करता था, आज टूट चुका है, टूटा हुआ है, टूट रहा है। यही है इस आन्दोलन का नतीजा। आन्दोलनकर्त्ता चाहे या नहीं चाहे विरोधी दल टूट चुका है, टूट रहा है। इस आन्दोलन करनेवालों की जो भी मंशा हो, पर नारा उठेगा विधान सभा भंग करो, वोट भंग करो, पार्टी भंग करो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस आन्दोलन में छात्र आन्दोलन की जिन मांगों के सम्बन्ध में हमलोग साथ थे वह जे० पी० रहित था। जे० पी० रहित आन्दोलन की मांग थी पेशाकर वापस लो, थोक व्यापार खतम करो और जे० पी० रहित आन्दोलन की उपलब्धि यह हुई कि पेशाकर वापस हुआ, थोक व्यापार खतम हुआ। आज जे० पी० सहित आन्दोलन है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि विरोधी दल टूट रहा है, आज हजारो-हजार नौजवान जेल के शिकन्जे में बन्द हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है और उनलोगों के साथ भी है जो चाहते हैं कि पार्टी भंग हो, वोट भंग हो। इस तरह आज हम दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समझें जिस तरह बाढ़ के समय में सांप और नेवला की जान जब खतरे में पड़ती है तो एक ही साथ शरण लेता है, उसी तरह आज विधान सभा की हालत हो गयी है। आज विरोधी दल और सत्ताधारी दल के लोग अपने को बचाने में लगे हुए हैं। आज जैसी परिस्थिति है, वह जनतन्त्र के लिए घातक है। इस तरह जनतन्त्र जिन्दा नहीं रह सकेगा, जनतन्त्र में विरोधी दल नहीं रहेगा तो जनतन्त्र नहीं रहेगा।

श्री विद्याकर कवि - सांप कौन है और नेवला कौन है ?

श्री भोला प्रसाद सिंह—सांप तो खुद ही बोल रहा है। तो मेरा यह कहना है कि यह जो आन्दोलन है वह गुमराह करने वाला है। इसलिए आन्दोलन के जरिए न तो भ्रष्टाचार मिटेगा और न महंगाई ही दूर होगी और न बिहार ही बदलेगा। चन्द्रशेखर बाबू मेरी बात सुनें। आन्दोलन के लिए दो शर्त होना चाहिए : एक कांग्रेस विरोधी और दूसरा वोट भंग न होना। आइए, इस तरह का मंच बनाइए। नपुंसक आन्दोलन से बिहार बदलने वाला नहीं है। आन्दोलन ऐसा होना चाहिए जो कांग्रेस विरोधी हो और वोट भंग न हो। अगर वोट रहेगा तो अनेक विधान सभाओं का जन्म होगा। इन्हीं दो शर्तों पर आइए और आन्दोलन कीजिए। आन्दोलन ऐसा नहीं होना चाहिए जो नपुंसक हो और गुमराह करने वाला हो। इस आन्दोलन से न तो भ्रष्टाचार मिटेगा और न महंगाई ही मिटेगी तो विरोधी दल की तरफ से इस तरह का आन्दोलन चलाना चाहिए कि कांग्रेस मिट जाय, साथ-ही-साथ भ्रष्टाचार भी मिट जाय। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जयप्रकाश जी बराबर कहते हैं कि विधान सभा के सदस्य वेतन पर, भत्ते पर पलते हैं। मैं पूछता हूँ कि आखिर हमलोग क्या करें ? चोरी करें, डाका डालें, सेंध मारें ? आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, लेकिन हमलोग तो अपने घर को जलाकर देश को बनाने में लगे हुए हैं। यह कहा जा रहा है कि विधान सभा के सदस्य विधान सभा की कमाई पर पलते हैं।

हमारे विन्देश्वरी प्रसाद मंडल हैं, जो पैसा उनको यहाँ मिलता है उससे कम पैसा भी मिलेगा तो वे यहां आकर बैठेंगे। तो इसमें महंगाई-भत्ता की बात करना बहुत बुरा लगता है, यह उचित नहीं है। हम जयप्रकाश बाबू से आग्रह करना चाहते हैं कि हमलोग विधान सभा से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि उससे हमारा सैद्धान्तिक विरोध है, मतभेद है, हम कोई वेतन भत्ता के लोभ में यहां नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजनीति की बात को लेकर दिल में दर्द होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विरोधी दलों का साथ १९४७ ई० से ही जेल का रहा है। कोई भी साल नहीं है जबकि संसोपा के लोग लाठी नहीं खाये, लड़ाई नहीं लड़े और जेल नहीं गये। हमलोग विगत २७ साल से महंगाई के खिलाफ लड़ते रहे, अन्याय के खिलाफ और आज हम बुरे हो गए हैं, गांधी मैदान के मंच पर जिन सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दिया उनको रहने नहीं दिया गया, उनको राजभवन में

डेलिगेशन में नहीं जाने दिया गया। आज २७ साल की कुर्बानी का नतीजा हुआ कि हम अछूत हो गए। जो २७ साल से दूध, मक्खन और शहद खा रहे हैं, जब हम जेल की कोठरी में बन्द थे, आज वे ही उपदेश दे रहे हैं कि राजनैतिक मंच पर मत बैठो, पताका मत लगाओ। उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने को विलीन कर दिया, लाठी खाया, मार खाया और जेल गया और आज हम और चौकीदार दोनों बराबर। यह आन्दोलन दिशाहीन है, इसको कोई दिशा नहीं है। एक बहाना है। उपाध्यक्ष महोदय, एक थे मौलाना रोशन अली। एक गरीब आदमी उनके पास फरियाद लेकर गया कि हमारी मुर्गी चोरी कर ली है किसी ने। हमारी मुर्गी दिला दें। रोशन अली ने मुर्गी चोर को कहा कि तुम्हे ६ महीने की सजा हुई क्योंकि तू ने मुर्गी चुराई है। मुर्गी वाले ने कहा कि हमारी मुर्गी दिलवा दें तो रोशन अली ने कहा कि तुम्हें भी ६ साल की सजा—तूने मुर्गी रखी और मुर्गी मेरे पास। तो ये आन्दोलन चलाने वाले भी कांग्रेस को ६ साल की सजा और विरोधी दल वालों को भी ६ साल की सजा और जनता मेरे पास। (जोरों की हंसी)

श्री विद्याकर कवि—बीच में मुर्गी इनको भी मिल गई है!

श्री भोला प्रसाद सिंह—हम चाहते हैं कि मेरी मुर्गी मेरे पास रहे और मुर्गी-चोर से मुर्गी मिल जाए।

श्री विद्याकर कवि—यह तो पुरुषार्थ और नपुंसकता पर निर्भर करता है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, १८ मार्च से आज तक इनका १३ करोड़ रुपया पुलिस व्यवस्था पर खर्च हुआ है। हमारे मुख्य मंत्री कहेंगे कि करोड़ नहीं पूरा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप ए० जी० ऑफिस से जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए कि कितना ओव्हर ड्राफ्ट हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने सुना सहस्त्रबाहु का नाम, जो अपने सहस्त्रबाहुओं से सहस्त्र काम करता था और आज हमारे मुख्यमंत्री भी सहस्त्रबाहु हो गए हैं। ये विद्यार्थियों से लड़ रहे हैं, डाक्टरों से लड़ रहे हैं, प्रेस से लड़ रहे है, अपनी पार्टी के अन्दर लड़ रहे हैं, जनता से लड़ रहे हैं, पता नहीं ये एक ही साथ किस किस से लड़ेंगे।

हमारी इनसे नेक सलाह है कि जिन विद्यार्थियों को आपने बन्द कर रखा है उनको तत्काल छोड़ दीजिए। धरना चल रहा है, अहिंसात्मक तरीके से उनका

आन्दोलन चल रहा है तो हिंसा पर आप न आयें। अभी तो ऐसा लगता है कि आप सिकन्दर आजम हैं। लेकिन मैं एक दोस्त के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतिहास देखें, इतिहास में भी आन्दोलनकारियों पर मीसा का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आप उन्हें मीसा में बन्द कर रहे हैं। आपने सर्चलाइट और प्रदीप को डीलिस्ट कर दिया। क्या श्री के० बी० सहाय और भोला पासवान शास्त्री का नाम हेड लाइन में नहीं छपता था ? आपको तुनुकमिजाज नहीं होना चाहिए। आपने सर्चलाइट और प्रदीप को डीलिस्ट किया है। इसको आप वापस लीजिए। सर्चलाइट और प्रदीप को जलाना, उसके सम्पादक को नौमिनेट करना और डीलिस्ट करना ये तीनों एक ही हाथ ने किया। आपके इर्द गिर्द रहने वाले चाटुकार हर रोज आपके घर पर जाते हैं और दरबार करते हैं। इस अवधि में मेरे दोस्त १९ रोज के लिए मुख्यमंत्री रहे, अब दूसरे दोस्त २९ दिन मुख्यमंत्री रहे जिनके साथ इसका साथ रहा और अब आपके साथ हैं और आपका जीवन है—२९ रोज।

*श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—उपाध्यक्ष महोदय, श्री शम्भु शरण झा के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं जो दूसरे सदन के सदस्य हैं और १९ रोज की मिनिस्ट्री के बारे में कह कर उनके एम० एल० सी० होने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।

श्री भोला प्रसाद सिंह—हमको न किसी शम्भु झा से मतलब है और न किसी बन्धु झा से मतलब है। हम तो गफूर साहब से पूछना चाहते हैं कि विधान सभा न भंग हो, इसके क्या उपाय हैं ? रास्ता पुलिस और सी० आर० पी० नहीं, बी० एस० एफ० नहीं है, विधायकों के घरों को प्रोटेक्टेड जोन में रखेंगे, यह भी नहीं रास्ता है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, कितने दिनों तक प्रोटेक्टेड जोन में रहेंगे ?

उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—मुझे दो मिनट और समय दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस रोज प्रोटेक्टेड जोन बनेगा हमारे जैसा आदमी नहीं रहेगा। आज सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि एक संस्था का है। वह संस्था है विधान-सभा। जब यह संस्था रहेगी तब ही आप रहेंगे, हम रहेंगे। गफूर साहब मुख्य मंत्री रहें या दारोगा बाबू मुख्य मंत्री रहें हमें इससे

कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जब विधान-सभा रहेगा तब ही कोई भी मुख्य मंत्री हो सकता है। यह जो आपके ओफिसर हैं यह राष्ट्रपति शासन चाहते हैं क्योंकि यह ओफिसर के लायक राष्ट्रपति शासन ही है। आप सी० आर० पी० या वी० एस० एफ० के बल पर विधायकों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। श्री जनक बाबू को डी० एम० के सामने लूटा गया, श्रीकांत झा को सी० आर० पी० के सामने घेराव किया गया। आपके ओफिसर उस समय क्या कर रहे थे। आप ओफिसरों के बल पर जीना चाहते हैं। आप बहुमत में हैं। आप यहाँ मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं। इंगलैन्ड मे हीथ ने मध्यावधि चुनाव करा दिया, आस्ट्रेलिया में वहां की सरकार ने ऐसा चुनाव करा दिया। इस हिन्दुस्तान में भी श्रीमती गांधी ने भी यह चुनाव कराया। यदि आप चाहते हैं कि बिहार में शांति स्थापित हो, तो मैं कहूँगा कि आप यहां रहें या नहीं रहें परन्तु विधान-सभा रहे, जनतंत्र रहे तो इसके लिए आप मध्यावधि चुनाव करायें।

उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया आप बैठ जायें। अब आप को कुछ भी नहीं कहने दिया जायेगा।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और समय दिया जाय।

उपाध्यक्ष—आपको एक मिनट भी समय नहीं दिया जायगा। आप बैठ जाइयें।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने श्री फुलेना राय का नाम पुकारा)

*श्री फुलेना राय—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है उसका मैं ताईद करता हूँ और साथ-साथ यह भी कह देना चाहता हूँ कि मेरे बारे में जो गलतफहमी फैलायी गयी है वह बिल्कुल निराधार और असत्य है। मैं ५ ता० को विधान-सभा आया था और उपस्थित होकर घर चला गया। उसके बाद मैंने जब समाचार-पत्र में देखा कि ५ तारीख को जो घटना घटी है, उसमें मुझ पर आरोप लगाया गया है। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ और विधान-सभा की मर्यादा को देखते हुए मैंने सोचा कि विधान-सभा में उपस्थित होकर ही अपने आपको सरेन्डर कर दूं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ। मैं एक महीने से बीमार था। मेरे विरुद्ध पुलिस

ने जो अभियोग लगाया है और मेरे पीछे पुलिस घूम रही है, इसलिए मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे पुलिस के साथ नहीं बल्कि किसी मजिस्ट्रेट के साथ किसी जगह भेज दीजिए जो कानून कहता है।

उपाध्यक्ष—यह आप उपाध्यक्ष को नहीं, मुख्य मंत्री को कहिए।

श्री फुलेना राय—मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता था।

उपाध्यक्ष—वह ठीक है। यह आपका हक है।

श्री ब्रज मोहन सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मेरे द्वारा जो संशोधन दिए गए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हमलोगों को सुनने का मौका मिलता है और इसपर धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव विधान-सभा में लिया जाता है। लेकिन इस वर्ष महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और उसपर धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव अजीब सा लगता है। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण १८ मार्च, १९७४ को होनेवाला था। उसके पूर्व विरोधी दल के नेताओं ने लिखित दिया था कि हमलोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और यह कि बहिष्कार कुछ मुद्दों पर और कुछ कारणों पर होगा। सरकार जो जनतांत्रिक सरकार है उसे विरोधी दल के नेता अपने दल के निर्णय से अवगत करा देता है तो तरीका यह है कि सरकार को चाहिए कि विरोधी दल के नेताओं के साथ सरकार बैठकर परामर्श करे और परामर्श के दौरान उनके मुद्दों और कारणों पर विचार करे, यदि वह विषय विचारणीय हो। और उन्हें विधान-सभा आने के लिए सरकार बुला ले। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं कि १८ मार्च, १९७४ के पूर्व छात्र नेताओं ने सरकार के सामने माँगें रखी थीं और वे माँगें बहुत ही सीमित थीं। उन सीमित माँगों को सरकार को मान लेने में कुछ नहीं जाता। यदि सरकार मान लेती तो वह आन्दोलन समाप्त हो गया रहता। लेकिन आज १८ मार्च के बाद आज ११ जून, १९७४ तक जो स्थिति आ गयी है वह स्थिति नहीं आती। बाद में राजनीतिक भावनाओं का प्रवेश हुआ। आप जानते हैं कि जब कोई आन्दोलन चलता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो तो उसके पीछे लोग आ जाते हैं और कुछ राजनैतिक बातें भी आ जाती

है और जब आन्दोलन में राजनैतिक बातें आ जाती हैं तो वह नियत्रण के बाहर हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, १८ मार्च, १९७४ का जो दृश्य था उसे हमने विधान-सभा के अन्दर में नहीं देखा, बाहर से ही हमें देखने का मौका मिला, चूँकि मेरी पार्टी ने उस दिन सदन से वहिष्कार करने का निर्णय लिया था। हमारे नेता ने सूचना दी थी कि महँगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में सदन का वहिष्कार किया जाय। लेकिन सरकार ने उसको नजर-अन्दाज किया। हमारे दल ने क्यों ऐसा निर्णय लिया ? आप जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसमें सरकार की सराहना की जाती है और सरकार के कार्यक्रम की बात रहती हैं इसलिए हमारे दल को उस अभिभाषण में विश्वास नहीं था। हमारे दल ने १९७२ ई० में सत्याग्रह किया था और सरकार को सूचना दी थी कि भ्रष्टाचार और महँगाई को मिटायी जाय। मेरा आन्दोलन, मेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी के बताये हुए, चलाये हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर था। केन्दीय सरकार का राजस्व भवन जो है, उसी में हमारे दल के लोगों ने धरना दिया था और यह सत्याग्रह महीनों तक चलता रहा। इस सत्याग्रह में लगभग हजारों लोग विधायक सहित जेल गये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को उसी समय सोचना चाहिए था। क्योंकि आगे आने वाली जो घटना घटती है उसकी जिम्मेवारी सरकार पर होती है। अगर कोई राष्ट्रीय दल है और महात्मा गांधी के चलाये हुए मार्ग पर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलता है और राष्ट्रीय समस्या को सरकार के सामने रखता है और उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाता है, तो सरकार को समझ जाना चाहिए।

लेकिन सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि आंदोलन ने भयकर रूप धारण किया। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जिम्मेवारी किस पर है ? इसकी जिम्मेवारी सरकार पर है क्योंकि १९७२ के सत्याग्रह की इन्होंने परवाह नहीं की और जेल को भरा गया था। उस समय सरकार कुछ ध्यान देती कि जनता का सत्याग्रह है, जनता मुसीबत में है तो आज ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उस समय कहा गया, यहां तक कि लोक सभा में ये बात उठायी गयी कि ये लोग राजनैतिक दल के लोग हैं, चुनाव में परास्त हो जाने के कारण फ्रस्ट्रेटेड हैं जिसके कारण सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी बात नहीं मानी गयी जिसका नतीजा हुआ कि इतने इंसान की जान गयी, करोड़ों

रुपयों की बर्बादी हुई। आज भी इस राज्य का विकास रुका हुआ है। पुलिस अधिकारी और सारे ऑफिसर विधान-सभा के बचाने में लगे हैं तो इसकी जिम्मेवारी किस पर आती है ? इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आती है।

(इस अवसर पर श्री कामदेव प्रसाद सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

इसके लिये सरकार को चाहिए था कि पहले वह सोचती जिसमें इतनी बड़ी बर्बादी नहीं हो। इतना बड़ा आंदोलन का रूप नहीं धारण करे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने पहले ही क्यों नहीं इस आंदोलन के नस को पहचाना कि जन-आंदोलन आने की भावना लोगो मे आ रही है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं. छात्र लोग मांग करते हैं, उनकी बातें और उनकी माँग को आप ठुकरा देते हैं तो हम कहां जायेंगे। सारे बिहार की जनता हमसे मांग करेगी, हमारे क्षेत्र की जनता जब हमसे मांग करेगी तो हमें मानना ही पड़ेगा। विधान-सभा का विघटन तो चलते-फिरते हो जाता है। मुख्य मंत्री को इस चीज को पहचानना होगा कि तह में क्या है ? यह आंदोलन विधान-सभा को विघटित कराने का रूप क्यों लिया ? जनता की आकांक्षा को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं, उनकी भावनाओं की मदिर को आपने इगनोर किया है। उनकी जो समस्या रखी गयी, विरोधी दल की ओर से जो सुझाव दिया गया, उसको आपने नजरअंदाज किया। आपकी बहुमत की सरकार है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुमत में रहते हुए आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसके लिये आपको सोचना पड़ेगा। जनता ने आपको बहुमत लोक सभा से लेकर विधान-सभा तक दिया, लेकिन आपका दल, पता नहीं, स्थायी सरकार क्यों नहीं दे सकी, जनता की आकांक्षाओं की पूर्त्ति नहीं कर सकी ? यदि आप उनकी समस्याओं को हल नहीं करते हैं तो आपको सरेन्डर करना ही पड़ेगा। एक दिन नौबत आयेगी कि हम इस्तीफा करेंगे या नहीं, हमारा दल इस्तीफा करेगा या नहीं, स्थिति ऐसी आ जायेगी कि सरकार को छोड़ कर भागना ही पड़ेगा। इसलिये जनता का रुख आपको पकड़ना ही पड़ेगा। हम किसी के प्रोटक्शन में रह कर विधान-सभा अटेन्ड नहीं कर सकते हैं। यह बहुत बुरा होगा कि इस स्थिति में विधान-सभा हम आएं। इसलिये स्थिति को आपको संभालना है, यदि आप सरकार चलाने में सक्षम हैं, सरकार चलाने की हिम्मत रखते हैं। बिहार में आपका बहुमत है, तो बिहार में शान्ति स्थापित कीजिए। हम अपने क्वाटर्स से आते हैं

तो बिना रोक टोक के विधान-सभा आने की छूट नहीं है और न क्वाटर्स में निस्संदेह रह सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों, जिन राष्ट्रीय समस्याओं पर हमारा दल समर्थन करता है, इस पर विचार करना होगा। वह एक ऐसी समस्या है कि श्री जयप्रकाश नारायण क्या सभी लोगों को इसे सोचना पड़ेगा। मँहगाई घटायी जाय, भ्रष्टाचार दूर किया जाय–इसका समर्थन सभी लोग करेंगे। अगर एक मामूली आदमी इस समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा करता है और कहता है कि बेकारी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार और मँहगाई को दूर किया जाय तो इसका समर्थन सभी लोग करगे।

अगर कोई कहता है कि भ्रष्टाचार को रोको तो सब कोई समर्थन देगा, अगर कोई कहता है कि कुछ करो या न करो लेकिन विधान-सभा का विघटन करो तो इसमें सोचना पड़ जायेगा। इन सारे मुद्दो पर हर दल समर्थन करता है। जो राष्ट्रीय मांगे हैं जैसे भ्रष्टाचार मिटाओ, बेकारी दूर करो, गरीबी मिटाओ तो इसम सब लोग साथ देंगे। केवल एक ही मुद्दा आता है और वह है विधान-सभा विघटन का, इसमें मतभेद है। मतभेद हैं इसलिये कि यह मांग हमारे लोकनायक श्री जयप्रकाश बाबू का है। इसलिये इस मांग पर हमलोगों के मन में सशय हो गया है। जन-समिति के द्वारा टिकट देने की बात उठायी जाती है। आप जब इस्तीफा करेंगे तो चुनाव के लिये फिर नहीं खड़ा होंगे, और जब चुनाव प्रणाली में सुधार होगा तब चुनाव होगा, सारे देश की सभा विघटित हो जाय, नया चुनाव किया जाय तथा चुनाव प्रणाली में परिवर्त्तन लाया जाय तब चुनाव किया जाय इन्हीं सब कारणों से रूकावट है। लेकिन जिस दिन नक्शा साफ हो जायगा उस दिन सब को सोचना पड़ेगा। मैं श्री जयप्रकाश बाबू की सराहना करता हूँ, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, मैं उनकी आलोचना करने के लिये नही खड़ा हुआ हूँ। हमारा दल है, हम भी एक सदस्य हैं, इसलिये हमलोगों को भी आज-या कल इसका शिकार होना है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब तक यह संशय है तब तक हमारा भी स्पष्ट निर्णय नहीं है। हम अंधकार में अपने को डालने को तैयार नहीं हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लोकमत का आदर करते हैं, जनता की मांग के सामने झुकेगें, हमें जनता के सामने सरेण्डर करना होगा और करेंगे भी। यह विधान-सभा भी जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता के सामने

इसको भी सरेण्डर करना पड़ेगा। जनता इस सभा का मालिक है, संविधान जनता बनाती है, इस देश और जनतन्त्र का मालिक जनता ही है। इसलिए जनता के सामने सब कोई झुकेगा। लेकिन विश्वास होना चाहिये कि यह विघटन की मांग जनता की है। जिस दिन यह आस्था हो जायेगी कि यह जनता की मांग है उस दिन सरेण्डर करेंगे। जब तक यह विश्वास है कि यह जनता की मांग नहीं है, उसका आन्दोलन नहीं है, दूसरे लोगों का आन्दोलन है, दूसरे लोगो के प्रभाव से यह आन्दोलन चल रहा है, तब तक हम सरेण्डर नहीं करेंगे। जो दल राष्ट्रीय दल है, जो जनता की भावनाओं को लेकर चलेगा वह सरेण्डर नहीं करेगा। आज के वातावरण को मुख्य मंत्री अपने काम से, अपने बढ़ते हुए कदम से प्रभावित कर रहे हैं। इस राज्य में आस्था पैदा हो इसके लिये मुख्य मंत्री ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये तेजी से कदम बढ़ाया है। आज भ्रष्टाचार के आरोप में जितने पदाधिकारियों को निलम्बित किया गया या कार्यमुक्त किया गया उतना किसी जमाने में नहीं किया गया है। यह तो एक मुद्दा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये सब कार्रवाई की गयी है। हमारे माननीय जयप्रकाश बाबू ने भी एक जन सभा में कहा कि वर्त्तमान मुख्यमंत्री इस ओर, समस्याओं के समाधान की ओर कदम उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह विवादास्पद बात हो जाती है कि आज यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है कि विधान-सभा को समाप्त किया जाय। ऐसा करने से तो फिर राष्ट्रपति शासन काल में पदाधिकारी वर्ग मनमाना काम करना शुरु कर देंगे। यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। राष्ट्रपति शासन काल में तो पदाधिकारियों के मन में प्रतिशोधात्मक भावना हो जायेगी और वे और भी मनमाना काम करना शुरू कर देंगे। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस विधान-सभा के जरिये जो कुछ भी आन्दोलन का रूप ले लेकिन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। अगर बर्बरता, हिंसात्मक प्रवृत्ति इस आन्दोलन में आ जाती है तो यह आन्दोलन बदनाम हो जायेगा और इस आन्दोलन के साथ हम नहीं रहेंगे। अगर यह आन्दोलन महात्मा गांधी के रास्ते पर, अहिंसात्मक रास्ते पर चलेगा, यहां की जनता हमारे सामने हाथ जोड़कर निवेदन करेगी, हमारे मनोबल को जीत लेगी और अपनी बातों से हमें कायल कर देगी कि यह जनता की मांग है तो हम सरेण्डर करने के लिय तैयार रहेंगे।

*श्री कामदेव प्रसाद सिंह (सभापति)—४ बजे तक माननीय सदस्यों को बोलने का समय दिया जायगा। ४ बजे से ५ बजे तक सरकार का जवाब होगा।

श्रीमती कृष्ण शाही—राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव जो आया है उसका मैं समर्थन करती हूं। राज्यपाल के अभिभाषण का संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो राज्यपाल के भाषण में बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला गया है और बहुत सारी चीजों की चर्चा की गयी है लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि अभी हाल में बिहार के दो प्रमुख दैनिक पत्रों-सर्चलाइट और प्रदीप को मान्यता सूची से हटा दिया गया है। यह एक दु.खद निर्णय है। सर्चलाइट का इतिहास भारत की स्वतंत्रता का इतिहास रहा है। हम, आप और सदन के सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सर्चलाइट ने स्वतंत्रता के लिये, देश की आजादी के लिये कितनी अद्वितीय भूमिका अदा की है। जब विदेशी सल्तनत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी तब उस समय निर्भीक, निष्पक्ष और क्रांतिकारी विचारों को जनता के समक्ष रखना सर्चलाइट का एकमात्र उद्देश्य था। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनकी सल्तनत थी, और जिस सल्तनत में सूर्यास्त नहीं हो पाता था उस समय में भी इन पत्रों को गैर-कानूनी ढंग से बन्द नहीं किया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया था। इस संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि नीति की रक्षा के लिये हमारे वर्त्तमान प्रधानमंत्री के पितामह पंडित मोती लाल नेहरू और सी० आर० दास पटना आये थे। हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े विद्वान जैसे डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० सच्चिदा नन्द सिन्हा और आचार्य बद्रीनाथ वर्मा आदि का भी उनसे संबंध रहा है। हमारे राजनीतिक जीवन में समाचार पत्रों का प्रमुख स्थान रहा है। हम, आप सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में प्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेस प्रजातंत्र में प्रहरी का काम करता है और इस प्रहरी पर जो आघात पहुंचाता है वह देश के लिये एक खतरा बन जाता है। आज जो यह तरीका अपनाया गया है वह अच्छा नहीं लगता है। यह तरीका सरकार को जन-विरोधी सरकार बना देता है।

मैं कुछ मौलिक प्रश्न के संदर्भ में सरकार से पूछना चाहती हूं कि इन दिनों पत्रों को मान्यता सूची से हटाने के पहले गृह विशेष विभाग ने सरकार को परामर्श दिया था। मान्यता सूची से हटाने के पूर्व सरकार ने क्या राज्य प्रेस ऐडवाईजरी काउन्सिल से परामर्श लिया। इन दोनों पत्रों के विरूद्ध ऐसा कठोर कदम उठाने से पहले क्या प्रेस काउन्सिल ऑफ इन्डिया से पूछा गया था? सरकार के द्वारा निर्णय लेने से पहले क्या उन पत्रों को चेतावनी दी गयी? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनका

जवाब सरकार को देना चाहिये। संसार का इतिहास बताता है कि जहाँ कहीं प्रेस की स्वतंत्रता एव प्रकाशन पर नियंत्रण एवं प्रतिबंध रहा वहां का प्रशासन अत्यधिक बदनाम हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि दोनों पत्रों को पुनः मान्यता की सूची में रखने के लिये विचार करे। प्रजातन्त्र की रक्षा नियम का उलघन करके नहीं किया जा सकता है। जो हमलोग दुहाई देते हैं प्रजातंत्र की रक्षा के लिये हम प्रजातंत्र की रक्षा तभी कर सकते हैं जब नियम का पालन करें। हमारे राज्य का नाम भी अग्रिम पंक्ति में आता है किन्तु संपन्नता के लिये नहीं, बल्कि विपन्नता और गरीबी की सूची में, शिक्षा नहीं अशिक्षा की सूची में। हाल में जो केन्द्रीय सरकार ने सर्वेक्षण कराया था उस रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्न में मिलावट इस राज्य में ६६.७ प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश में ६३.४ प्र०, मध्यप्रदेश में ५५.७ प्र०, आसाम में ५४.७ प्र०, राजस्थान में ४६.७ प्र०, उड़िसा मे ४१.८ प्र०, बम्बई मे ४१.४ प्र०, मैसूर में ४०.१ प्र०, आंध्र में ३७.८ प्र०, दिल्ली में ३७.० प्र०, वेस्ट बंगाल में ३२.३ प्र०, केरल में २६.४ प्र०, पंजाब में २२.२ प्र०, तामिलनाडू में २४.९ प्र०, और उत्तर प्रदेश में १९.६ प्र० है। इसमें बिहार सभी राज्यों से आगे है। इस प्रकार मैं यह कहूँगी कि ईमानदारी का स्तर कितना नीचे चला गया है। हाल में बिहारके चेचक ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके डब्लू० एच० ओ० के प्रतिनिधि ने बताया कि अन्य सभी प्रांतों में जितनी मृत्यु हुई है उसकी एक चौथाई बिहार में हुई। क्या स्वतंत्रता के २७ वर्षों के बाद भी यह स्थिति हमारे लिये शर्म की बात नहीं है? १९६६ में जब यह महामारी बिहार में इतनी अधिक नहीं थी तो केन्द्र से अनुदान के रूप में ४५ लाख रुपया मिला था। लेकिन सही ढग से उस रुपये का सदुपयोग नहीं होने के कारण, बैड इम्प्लीमेन्टेशन के कारण केन्द्रीय सरकार ने उस अनुदान को काटकर दो लाख पर पहुँचा दिया है। अभी हाल में सम्भवतः यह राशि फिर बढ़ा दी गयी है लेकिन यदि फिर राशि का सदुपयोग नहीं हुआ तो भय है कि अनुदान शून्य न हो जाय, फिर तो बिहार सरकार यह दुहाई देगी कि आर्थिक संकट, राशि के अभाव में चेचक जैसी महामारी की रोकथाम नहीं हो सकी। छूत की बीमारियों के लिये प्रान्त में अस्पताल नहीं के बराबर है। परिणामस्वरूप जेनरल वार्ड में ही अभी भागलपुर में चेचक-ग्रस्त मरीजों को रखा गया।

अतः सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इस ओर ध्यान दे क्योंकि कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेवारी जनता को स्वस्थ जीवन ही प्रदान करना है।

श्री टीका राम मांझी—सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो हमारे विरोधी दल की ओर से श्री चन्द्रशेखर सिंह ने संशोधन दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति तथा कार्यक्रम की जो झलक मिलती है, उसे देख कर मैं वहुत उदासीन हूँ। हमारे छोटानागपुर की उन्नति की बात कहीं नहीं है। छोटानागपुर स्वशासी प्राधिकार का गठन कर सरकार ने हमारी जनता के साथ एक मजाक किया है। इस राज्य में वहुत से निगम बनाये गये हैं, जैसे पथ परिवहन निगम, उद्योग निगम आदि, उनको अधिकार दिया गया है किन्तु छोटानागपुर एवं संथालपरगना स्वशासी प्राधिकार को कोई भी अधिकार नही दिया गया है। अन्य निगमों को अपनी निधि है, अपनी स्थापना है, अपना वैंक लेखा आदि है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि छोटानागपुर और संथालपरगना के लिये जो स्वशासी प्राधिकार बना है, उसको अपना निधि, वैंक लेखा, अपनी स्थापना कुछ नहीं है। इसलिये वहां की जनता को इस पर विश्वास नहीं है और इमीलिये इसकी वैठक में अधिक-से-अधिक सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्या सरकार इस स्टेप-मदरली ट्रीटमेन्ट को छोड़ना चाहती है।

सभापति महोदय, इन्हीं कारणों से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहां पर जो बिहार का बजट तैयार होता है, उसमें छोटानागपुर एवं संथालपरगना के लिये अलग बजट तैयार हो।

सभापति महोदय, अखबारों में मैंने देखा है कि गफूर साहब चोरबाजारी करने वालों को कड़ी-से-कड़ी सजा देना चाहते हैं, किन्तु अभी तक ये सजा दे नहीं पाये हैं। अभी एक घटना का जिक्र मैं कर देना चाहता हूँ जिससे कि इनकी कथनी और करनी का पता चल जाय। फरवरी, १९७४ में मारुफगंज पटना सिटी में १४ थोक व्यापारियों के यहां से बनस्पति का जाली परमिट मिला और कागज बरामद हुआ, लाखों रुपये के बनस्पति को चोरबाजारी में वेचने के लिये सभी सावूत मिले और इस तरह के १४ केस पटना सिटी में अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट में गया, किन्तु अब राजनीतिक दबाव के कारण यह खतम होने वाला है और

सबों को बेल पर छोड दिया गया है। इन पर डी० आई० आर० मीसा कुछ भी नहीं लागू किया गया।

सभापति महोदय, जमशेदपूर में एक मार्केटिंग औफिसर है श्री एस० के० घोष, उनके काले कारनामों के बारे में कौन नहीं जानता है। वहाँ के नागरिक वहां के वकील और जितनी भी वहाँ की जनता है सभी जानते हैं कि वे क्या-क्या करते हैं और उनके खिलाफ शिकायत भी है। मैं भी वहाँ का एक सदस्य हूँ। एक वकील पिछले दिसम्बर महीना में ५ तारीख से लेकर ६ तारीख तक मुख्य मंत्री को, एडूकेशन मिनिस्टर को, वहां के कमिश्नर को तथा चीफ सेक्रेटरी को लिखकर दिया कि एस० के० घोष को वहां की जनता को इतना लूटने का छूट नहीं दें। इसी तरह से उन्होंने सिमेन्ट और मोटर टायर में करोड़ों रुपये कमाया और अभीतक उनपर कोई कारंवाई नहीं हुयी। श्री एस० के० घोष कभी अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं, वे दिन में मुश्किल से ५ मिनट कार्यालय में रहते हैं और बाकी समय सेठ-साहूकारों के साथ सुरा सुन्दरी के बीच होटल में अपना समय बिताते हैं। जब काफी शिकायत उनके खिलाफ की गयी तो उनपर जो आरोप थे उसकी जाँच करने के लिये शायद वहां के कमिश्नर श्री एस० के० घोष को दिया, लेकिन हुआ, चोर-चोर मौसेरा भाई करके कोई कारंवाई नहीं की गयी। इसलिये जितना भी राशन और एफ० सी आई० का गेंहूँ जनता के लिये आया वह वहाँ के कमिश्नर की देखरेख में काला बाजार में जाता है। एक ट्रक गेंहूँ एक सेठ के यहाँ जो अग्रवाल था, रखा गया, जब धालभूमगढ़ के थाना प्रभारी ने इसको पकड़ा तो कमिश्नर के औफिस से आर्डर दिया गया कि इसको तुरत रिलीज कर दीजिये यह सीड के लिये है। लेकिन हम इसको पता लगाये तो पता चला कि यह गेंहूँ सीड या बीज के रुप में किसी किसान को नहीं बांटा गया बल्कि काला बाजारी करने वाले चन्द भर लोगों के बीच बंट गया। इसलिये मेरा सरकार से कहना है कि आप जो कहते हैं उसको प्रैक्टिकल रुप दीजिये, नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, और जन आंदोलन और कड़ा होगा।

सभापति महोदय, मैं एक सर्किल औफिसर के बारे में कहना चाहता हूँ कि वह सर्किल औफिसर अकेले दो अंचल का इंचार्ज है घाटशीला और धालभूमगढ़ और उनका नाम है श्री जितेन्द्र प्रसाद। उनको बार-बार कहने पर भी राशन का गेंहूँ वहाँ के पंचायत या सरपंच को नहीं दिये जिससे कि उसका वितरण वहां के लोगों में हो सकता। वहाँ की जनता ने कई बार अंचलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन

किया कि हमारा राशन का गेंहूं जो हमको मिलना चाहिये वह हमारे मुखिया और सरपंच को दे दो लेकिन जनता की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले मई महीना में जब धालभूमगढ़ की जनता ने सप्लाई इंसपेक्टर को एक राशन डीलर श्री वेद प्रकाश अग्रवाल की दुकान जांच करने को मजबूर किया तो पता चला कि उक्त सेठ रघुनाथडीह ग्राम पंचायत का सभी राशन हजम कर बैठा है। जब अंचलाधिकारी से कहा गया कि उस सेठ को थाना में डालिये तो अंचलाधिकारी ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। जब हमको मालूम हुआ और लोग हमारे पास आये तो हम वहां गये और अंचलाधिकारी से कहे कि उसको जेल में डालिये और उसपर ऐक्शन लीजिये तो वह अंचलाधिकारी जबाव देता है कि सेठ-साहुकारों को पकड़ने और उसके खिलाफ कारंवाई करने के लिये सरकार ने नहीं कहा है, इसलिये हम कोई कारंवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो चोरी करते हैं उसपर आप ऐक्शन लीजिये। आप सिर्फ बयान ही नहीं दीजिये बल्कि भ्रष्ट औफिसरों पर कारंवाई कीजिये नहीं तो मामला बहुत गंभीर हो जायेगा। सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ६ अप्रील को हमारे सिंहभूम जिला के मनोहरपुर में आदिवासी पर गोली चलायी गयी, जिसमें एक की मृत्यु हो गयी और ४ घायल हो गये। उनका क्या कसूर था ? कसूर यही था कि वे जंगल के ठीकेदार के यहां काम करते थे, वे कहते थे कि बारह-चौदह घन्टा काम नहीं करेंगे, ८ घन्टा काम करेंगे और डेढ़ रुपया के बदले ३ रुपया मजदूरी दी जाय। इसके लिए इन्सपेक्टर आई० डी० सिंह और सब-इंसपेक्टर वैजनाथ सिंह ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी और उसका परिणाम हुआ है कि इलाके में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है जिसका जिक्र मैं सदन में कर देना आवश्यक समझता हूँ। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये और दोषी पदाधिकारियों को सख्त सजा मिलनी चाहिये।

मंत्री महोदय की ओर से ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के संबंध में चिट्ठी दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि जिस-जिस गांव की आबादी १५०० से अधिक हो उनकी सूची दें, वहां यातायात की व्यवस्था सरकार कर देगी लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि डुमरिया ब्लौक टी० डी० ब्लौक है, वहां जाने के लिए सड़क नहीं है, जिसके चलते वहां ब्लौक का काम नहीं होता है, उस ब्लौक का काम मूसाबानी में होता है।

अत: मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों पर ध्यान देकर सरकार अविलम्ब कार्रवाई करे।

*श्री जयनारायण—सभापति महोदय, सदन में जो राज्यपाल के भाषण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूँ। आज जिन मुद्दों को लेकर विशेष परिस्थिति में सदन में विचार व्यक्त किए गए हैं उन पर बहुत अधिक प्रकाश डालने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हमारे जन-जीवन से संबंध है और जिसका जनतंत्र के नाम पर दो तरह की बातें की जाती हैं उन विषयों पर बिना विचार व्यक्त किए भी रहा नहीं जाता। आप जानते हैं कि १६६६ में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ बल्कि एक खंड ने बहुमत से उनका समर्थन किया और राष्ट्रीय मोर्चा के आधार पर एक नया प्रगतिशील दल, प्रगतिशील तबके के लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया। उसमें था कि २५-२७ वर्ष में प्रगति नहीं हुई, गरीबी बढ़ती चली जा रही थी, जिन लोगों के नाम पर आजादी ली गयी थी उनको लाभ नहीं हो रहा था उन सारी चीजों को बदलने की नीति के आधार पर, बदलने के मनसूबे के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा बना और जिसके समर्थन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को नयी दिशा दी, नया नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व का नए मार्ग पर पूरा समर्थन १६७१ के लोक-सभा के चुनाव में और १६७२ में विधान सभाओं के चुनाव में हुआ। उसका उपयोग जिस ढग से किया गया उसी का असर आज हम इस आन्दोलन के रूप में देखते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, जो सत्ता प्राप्त हुइ केन्द्र में और राज्यों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, जो उन्होंने वादा किया उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ६५ प्रतिशत गरीब लोग यहां रहते हैं उनका विशेष ध्यान रखकर यहां की आर्थिक, सामाजिक संरचना होगी और अभी तक हरिजनों, आदि-वासियों, बैकवार्ड क्लास के सारे लोगों को जो सताया गया है, अपनी सारी घोषणा के बावजूद २५ वर्षों में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पायी, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसको करना मुनासिब समझा और एक नयी दिशा दी। १६६७ के डिबेकेल के बाद, १६६६ में देश को नयी दिशा मिली, १६७१ में कार्यक्रम बना उसी के ३ वर्ष बाद कुछ तत्वों ने ऐसा आन्दोलन छेड़ा जो बिहार में चल रहा है और जिसको वे जनआन्दोलन कहने की हिमाकत रखते हैं। तो क्या हमारी दिशा गलत है। या हमारी वह गलत दिशा है या उस दिशा में हमने प्रगति नहीं की है, कुछ

पहल नहीं की है जिससे जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया सत्ता प्राप्त करने में, उनको हम कुछ लाभ नहीं पहुँचा सके। यह सत्य है कि इस आन्दोलन में जो समर्थक हैं या जो नेता हैं उनको यही गलत चीज बल दे रही है। १९६९ तथा १९७२ में हमने जो दिशा स्वीकृत की थी उसके पूरा नहीं होने के फलस्वरूप ही यह आन्दोलन शुरू हुआ है। इसमें हमारी कमजोरी यह थी कि जिन्होंने हमारा समर्थन किया था उसका विश्वास हम नहीं प्राप्त कर सके। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो पनचानबे प्रतिशत लोग हैं उनके पक्ष में लाभ नहीं पहुँचा सके बल्कि जो पाँच प्रतिशत लोग हैं उनके पक्ष में ही हमारा कार्य हुआ। इस तरह हमारी जो कमजोरी थी उसके कारण यह आन्दोलन हुआ है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह आन्दोलन जनतांत्रिक परम्पराओं पर एक चोट है या विधान-सभा पर एक चोट है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जनतांत्रिक परम्पराओं पर चोट नहीं है, विधान-सभा पर चोट नहीं है बल्कि बिहार की जनता का जो प्रतीक है उसपर यह चोट है। चाहे हमारी पार्टी की सरकार बने या विरोधी दल की सरकार बने यह विधान-सभा उसपर अपना अंकुश रखती है। इस विधान-सभा में जितने दल हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वे जनतंत्र में अपना विश्वास प्रकट करने के लिये बैठे हुए हैं। इस देश में आन्दोलन की जो लड़ाई चंपारण में १९१७ में शुरू हुआ था उस समय देश की मूर्तमान शक्तियों ने एकजुट होकर काम किया था वही शक्तियाँ फिर एक-जुट होकर जनतंत्र का झंडा बुलंद करने को तैयार हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वह जनतंत्र की रक्षा के लिये बैठे हुए हैं।

कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो मन्त्रिमंडल गुट के विरोधी हैं और दूसरे दल के जो लोग हैं जिन्होंने जनतंत्र के नाम पर इस आंदोलन का विरोध किया है, जिस बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई शुरु की थी आज वह बिहार गौरव का अनुभव कर सकता है, सीधे जनतंत्र पर चोट है, ९५ प्रतिशत जनता की आवाज को बन्द करने की साजिश है। बिहार ने गुजरात के बाद इस आंदोलन को बन्द करके पूरे देश में इस तरह के आंदोलन का रास्ता बन्द किया है। इसलिये बिहार के इस बिहार विधान-सभा का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। बिहार के सभी जनतंत्र प्रेमियों ने एक जुट होकर हमलोगों को चुनौती दी है जिन लोगों ने समाजवादी नकाब रखकर राजनैतिक चश्मे को स्थान दिया हैं। राष्ट्रीयकरण पर व्यक्त किये गये विचारों को देखिये, प्रिवीपर्स पर व्यक्त किये गये विचारों को देखिये या

हाल में पटने में जो कुछ हुआ उस पर व्यक्त किये गये विचारों को देखिये। बिहार की जनता इसका पर्दाफाम करेगी कि एक तरफ भूमिसुधार का नायक बनने की मनोकामना रखने वाले दूसरी तरफ भूमिसुधार कार्यक्रम को रोकने का नकाब पहननेवालों का। उन्होंने दलील पेश की थी- इस देश में जमीन का राष्ट्रीयकरण हो, जमीन बँटने से हमको कोई मतभेद नहीं है, जमीन को लेकर आंदोलन चलायें। इसका वे समर्थक हैं कि गाँवों में सब लोग टूटें। लेकिन प्रशासनिक यंत्र पर मनोपली है, दबाव है। उसी पालकीवाला के साथ समाजवादी जनतंत्र के नायक ने इस पृष्ठ-भूमि को कायम किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज इस आंदोलन से इस राज्य में, इस देश में कुछ होने को नहीं है। इस राज्य बिहार में या पूरे देश में उनका यह राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, १८ तारीख को जो घटना घटी भ्रष्टाचार निवारण संबंध में अगर यह स्थिति रहती तो राज्य के लिये अहितकर होता। चाहे गफूर साहब का मंत्रिमंडल हो या दूसरे का, लेकिन भ्रष्टाचार और मंहगाई का मुकाबला करना होगा। आज सारे प्रशासन में जिस तरह का भ्रष्टाचार फैल गया है, इसकी आवश्यकता है कि इसका मुकाबला डटकर किया जाय। आज भ्रष्टाचार, मंहगाई और बेकारी को दूर करने के लिये किसी तरह का आन्दोलन होता है तो वह दूसरी पार्टी के बनिस्पत कांग्रेस के लिये ज्यादे हितकर है। इस भ्रष्टाचार के पीछे पूँजीपति का हाथ है, यह पूँजीपति के प्रभाव का फल है। जब तक ये पूँजीपति सत्ता के साथ घुसे रहेंगे तबतक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, गरीबी दूर नहीं होगी। लेकिन यह सही है कि यह ज्यादे दिन तक चलनेवाला नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज जन आक्रोश की लहर फैल गयी है। अतः मुख्यमंत्री से आग्रह है कि भ्रष्टाचार के जो केन्द्रबिन्दु हैं, जहां से यह फैलती है, उसे कैसे मिटाया जाय, इस पर भी ध्यान दें।

ऐसी बात नहीं है कि एक सप्लाई इन्सपेक्टर के चलते बिहार डूब रहा है। आपके सारे प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह कि बहुमत जिनका भी हो लेकिन इस विधान सभा में कोई भी सदस्य आवाज उठाते हैं और वह बिहार की जनता से सम्बन्धित है तो आप उनपर विचार करें तो सभी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन वे अंकुश आप पर रखेंगे कारण आप जो वादा करके आये हैं, उसका पालन करें।

श्री रघुनन्दन प्रसाद—महोदय, मंहगाई पराकाष्ठा तक पहुंच गयी है। चावल तीन रुपये सेर, करुतेल १४ रुपये सेर और कोयला १०-११ रुपया मन बिक रहा है। गेहूँ, सोडा, साबुन तो मिलता नहीं है—लोग मंहगाई से तबाह हैं। जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव, नवजवान लड़के बेरोजगार पड़े हुए हैं। खेतों में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले इस मंहगाई से बेचैन हैं। महोदय, खेती करने के लिये सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनको काफी दाम पर सारी वस्तुएं खरीदना पड़ता है। महोदय १९७१-७२ में जो वादा किया गया था—इन्दिरागांधी ने वादा किया था कि हम गरीबी को हटायेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका और वह वादा का वादा ही रह गया।

महोदय, स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गयी है और इस अशांत वातावरण का विरोधी पार्टियां फायदा उठाना चाहती है—कुछ नाजायज ढंग से फायदा उठाना चाहती है जिसमें जनसंघ भी एक पार्टी है। इसको डिमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। इसको सिर्फ डिक्टेटरशिप में विश्वास रह गया है और वे लोग नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। यही कारण है कि जनसंघ के ११ सदस्य जनसंघ पार्टी से अलग हो गए हैं। महोदय, आज मंहगाई और भ्रष्टाचार से जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज मंहगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी का मुख्य कारण, मेरे जानते, सरकार की गलत नीति है। इसको दूर करने के लिये सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। महोदय, कहा जाता है कि मंहगाई वर्ल्ड-फेनोमेनन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जितनी मंहगाई बढ़ी है, उतनी मंहगाई दूसरी जगह नहीं बढ़ी है। इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। यह सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हुआ है। आज का आन्दोलन इसी का नतीजा है। छात्र आन्दोलन जिसका नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, वे कहते हैं कि विरोधी पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिये, विधान सभा को भंग करना चाहिए। मुझे पता नहीं चलता है कि इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है। महोदय, बिहार विधान-सभा को जो भंग कराना चाहते हैं उनके जन नायक को मैं कहना चाहता हूं कि बिहार विधान-सभा को भंग करा देने से मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कैसे बन्द होगा। यदि विरोधी पार्टी के ८०-८२ सदस्य इस्तीफा दे भी देंगे तो विधान-सभा कैसे भंग हो सकती है?

इस तरह आज जन-नायक की पदवी जिन्हें दी जा रही है, उनका समय-समय पर का स्टेटमेन्ट यदि देखा जाय तो विरोधाभास ही मिलेगा। उन्होंने देश द्रोह का भी काम किया है। आपको मालूम है, एक बार उन्होंने कहा था कि जम्मू-काश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाय और एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि याहिया खाँ जो कर रहा है उसकी सराहना की जा सकती है। इससे मालूम होता है कि वे अधिनायकवाद की ओर जा रहे हैं। इस लीडरशीप में मैं जाना नहीं चाहता हूँ और इसीलिये हमलोग जनसंघ के ११-१२ विधायक उनके नेतृत्व का विरोध किया और पार्टी से रिजाइन दे दिया, उम्मीद है जनता इसकी प्रशंसा करेगी।

*श्री शम्भू शरण ठाकुर—सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण के प्रति जो धन्यवाद-ज्ञापन का प्रस्ताव पेश है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इस सिलसिले में समय कम रहने के कारण मैं कुछ ही विषयों पर अपनी बातें कह सकूंगा। मैं आपके माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार और वर्तमान नेतृत्व से अपेक्षा करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार के सामने यहां का न केवल अस्थायी समस्याओं के बारे में अपनी बात कहे बल्कि स्थायी समस्याओं के बारे में भी अपनी बात रखे। आज केन्द्रीय सरकार बिहार के साथ विमाता जैसा व्यवहार करती है। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता श्री राधानन्दन झा ने आंकड़ा पेश करते हुए न केवल केन्द्रीय ग्रान्ट के बारे में ही कहा, बल्कि यह कहा कि केन्द्रीय ग्रान्ट ठीक से नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा केन्द्र द्वारा कोमर्शियल बैंक में कितना डिपोजिट हुआ है और अपेक्षाकृत इस राज्य में कितना इनभेस्टमेन्ट हुआ जिसके कारण यहां पर औद्योगिक प्रगति अपेक्षाकृत कम हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने बिहार के विपन्न अवस्था के बारे में अपनी बात रखे और केन्द्र से अतिरिक्त असिसटेन्स मांगे जिसके जरिए यहां की समस्या का हल हो सके। सभापति महोदय, विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विचार रखे गये हैं और कहा गया है कि किन कारणों से बिहार को अतिरिक्त असिसटेन्स चाहिए। मेरा कहना है कि यहां पर शिडिउलकास्ट और शिडिउल ट्राइब का पोपुलेशन दूसरे राज्यों से ज्यादा है, उनका परसेन्टेज बिहार में अधिक है। बिहार में इनका परसेन्टेज २७·९ है जब कि ओल इन्डिया लेभेल पर २१ परसेन्ट है। इसलिए इसको देखते हुए भी केन्द्रीय सहायता अधिक मिलनी चाहिए। बिहार का अपना एक एकोनोमिक

करैक्टर है। आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया है उसके अनुसार सारे देश के मुकाबले में बिहार में केवल १० प्रतिशत लोगों को नागरिक सुखसुविधा प्राप्त है। इसमें से आधी आबादी उत्तर बिहार की है जहाँ ५ प्रतिशत लोग ही शहर में रहते हैं और उनको नागरिक सुखसुविधा प्राप्त है। तो वेलफेयर स्टेट में ऐसी स्थिति है कि बिहार की अधिकतर आबादी इससे वंचित रह जाती है मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार को जो पावर्टी लाइन है और देश के विभिन्न राज्यों की जो पावर्टी लाइन है, दोनों में अनुरुपता होनी चाहिए। जो २० रु० पाने वाले व्यक्ति हैं उनको भी पावर्टी लाइन के नीचे रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो केन्द्र का आंकड़ा है वह ७ प्रतिशत है, बिहार का ७७ प्रतिशत है। इससे यह जान पड़ता है कि बिहार की उपेक्षा अनेक वर्षों से होती रही है। अर्थ शास्त्री तथा दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि आवश्यकता पर बल दिया जाय। मेरा यह कहना है कि भारत में जितनी मिनरल सम्पदा है, ज्यादातर बिहार में ही है इसलिए इसकी उपयोगिता होनी चाहिए थी और उसका उपभोग करना चाहिए था। लेकिन २५ वर्षों के शासन में इसकी कोई उपलब्धि नहीं हो सकी जिसके कारण यहां पर औद्योगिक इनफ्रा स्ट्रक्चर हुआ। यही कारण है कि सिंचाई, बिजली, एडुकेशन और कम्युनिकेशन का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि देश के अन्य भागों में हुआ। दूसरे राज्य की तुलना में बिहार में इसकी मात्रा कम है। यही कारण है कि जिस तेजी के साथ यहां पर आर्थिक विकास होना चाहिए था उस तेजी के साथ नहीं हो सका। केन्द्रीय सरकार से आपका अनुरोध होना चाहिए कि आपको अधिक आर्थिक सहायता मिले जिससे आप बिहार की विपन्नता को दूर कर सकें। आज बढ़ती हुई आबादी के साथ यहां का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग गिरता जा रहा है। सभापति महोदय, आज बिहार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विरोधी दल के नेता श्री चन्द्रशेखर सिंह ने भी इस पर प्रकाश डाला था। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पिछले वर्षों में अपनी प्रगतिशील नीति के माध्यम से हमने कुछ सफलता भी प्राप्त की है। गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। सीमित साधनों से आवश्यकताओं की पूर्त्ति हो और जनसंख्या को सुख सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए नीति में परिवर्तन लाना जरुरी था। इस सिलसिले में हमने कई कदम उठाया, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स को समाप्त करना, भूमि सुधार आदि। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से

प्रगतिशील कदम उठाये गए हैं जैसे लालफीताशाही और नौकरशाही को खतम करना। जो प्रतिक्रियावादी थे उन लोगों ने इसका विरोध किया जिसके कारण हमारी गाड़ी जहां की तहां रुकी रही। इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यू० पी० की सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ मुनाफाखोर और अपनी आवश्यकता से अधिक जमा रखने वाले के साथ जिस कड़ाई के साथ वर्ताव किया है उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर अन्न की काफी रिकभरी हुई। यहां पर भी उस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए। इस राज्य में आज हाहाकर मचा हुआ है, आवश्यकता की वस्तुएं जैसे तेल, साबुन, किरासन तेल आदि आज बाजार से गायब हैं और दुकानदार मनमाना ढंग से दाम वसूल रहे हैं। बेगाब से समस्या का हल नहीं हो पायेगा। सिर्फ मूल्य-वृद्धि ही राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि डेफीसीट फाइनैंन्सिग भी समस्या है। मूल्य-वृद्धि के दो कारण हैं एक है कृत्रिम, जैसे सामान को छिपा देना। और दूसरा है डेफीसीट फाइनैन्सिग। इस प्रकार मुद्रास्थीति से भी मूल्य-बृद्धि पर असर पड़ता है। मेरा कहना है कि केन्द्र ने पांच-वर्षों में १५० करोड़ का डेफीसीट फाइनैन्सिग किया। द्वितीय और तृतीय योजना में उसने ८०० और १२०० करोड़ का अतिरिक्त डेफीसीट फाइनैन्सिग किया। ऐसी उम्मीद की गयी थी कि कन्जम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा; लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। नतीजा यह हुआ कि मूल्य बृद्धि हुई। आज ब्लैक मनी १२०० करोड़ से ३ हजार करोड़ तक हो गया है, और यह रकम समय-समय पर समस्या पैदा करती रहती है। जो भी वितरण के लिये आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन्हें एक बार खरीद ली जाती है।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—१२ हजार करोड़ का आंकड़ा कहाँ से मिला?

श्री शम्भु शरण ठाकुर—आर्थिक परम्पराओं से और विभिन्न पत्रिकाओं आदि से आकड़े आते रहे हैं, जो एलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, उनकी जो सरकार होगी तो उनके सामने यह समस्या आयगी ही। जो नेतृत्व है उसके लिये यह चुनौती है कि राज्य की जनता को संसदीय प्रणाली के माध्यम से जो भी स्थिति है उनकी आवश्यकताओं को मुहैया करेंगे। राज्य और जनतंत्र में चुने हुये प्रतिनिधियों की; चाहे जो भी भूमिका हो उनके सामने यह कर्तव्य है कि वे इसका सामना करें। गुजरात विधान-सभा के विघटन होने के पश्चात् निश्चित रूप से आज मूल्यों में

आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नौकरशाही और लालफीताशाही ने विघटन का लाभ उठाया, पूँजीपति और मुनाफाखोर जो जनतंत्र के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं, उन्होंने इसका लाभ उठाया। सवाल दूसरा उठता है कि प्रगतिशील नीतियों ने बराबर मार खाया है। जो ससदीय जनतत्र के चुनाव के तरीके हैं, उनमें कुरीतियां हो सकती हैं, लाठी भाला का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जनता जनतांत्रिक पद्धति से अपनी सम्पूर्ण भावना को व्यक्त करती है। आज देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जेहाद छेड़ा गरीबी और पिछड़ेपन को हटाने के लिये और आज हम जिस एकनामी स्टेज से गुजर रहे हैं, वह नेशनल गवर्मेंट का स्वरूप न हो लेकिन शेडो की तरह जनता की सुविधा बढ़ाने की जिम्मेदारी विभिन्न दलों के प्रतिनिधि पर हो सकती है जिस दर पर मूल्यों में वृद्धि हो रही है, विदेशों से हमें समय-समय पर सहायता मिलती रही हैं, हमें इसे छोड़ना पड़ेगा।

दुर्भाग्य की बात है कि जिस क्राइसिस से हमलोग गुजर रहे हैं जिसका निस्पादन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही हो सकता है आज उसी को सफाया करने की बात आ खड़ी हुई है। रावण-अंगद संवाद हो रहा था। अंगद ने पूछा कि क्या तू वही रावण है जो सबसे बड़ा विद्वान है, या सीता को हरण करनेवाला रावण है या वह रावण है जिसे बाली ने ६ माह तक अपने कांख में दबा कर रखा था। उसी तरह आज स्वतंत्रता के आन्दोलन में श्री जयप्रकाश नारायण ने राजनीति के विभिन्न पक्षों पर अपना विचार दिया था, पाकिस्तान के अयूब के साथ कनफ्रोंटेशन की बात उठाई और फिर बगला देश के बारे मे अपना विचार व्यक्त किया। पत्रकार सम्मेलन में दुनिया के लोगों के सामने इसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया जिसे दुनियां के लोगों ने मान लिया और ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि उन्होंने इन्दिरा गांधी के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कश्मीर और नागालैंड के बारे में इनका क्या विचार रहा। उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, उनके प्रति आक्रोश है जिसे वे समझें। जैसा कि बिनोवा जी ने कहा है कि वे ईमानदार हैं और अगर वे अपनी गलती को समझ लेंगे तो वे इस रास्ते को त्याग कर आन्दोलन को बन्द कर देंगे। यह बात विनोवा जी ने कहा है जो उनके गुरु हैं। ऐसे समय में जनतत्र की रक्षा के लिए और प्रगतिशील कार्यक्रम के लिए आज नौकरशाही और राष्ट्रपति शासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जनतंत्रीय प्रणाली में जो एलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्हस हैं, उन्हीं पर

भरोसा किया जा सकता है। आज विधायक बने रहने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में प्रश्न यह है कि जिस काम के लिए हमने शपथ ली है जिसके माध्यम से राजनीतिक दौर में काम करना है और इसे समाप्त करना हमारे लिए कायरता की बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार दृढ़ता के साथ इसमें अडिग और निडर होकर इसका मुकाबला करेगी।

श्री बागुन सुम्ब्राई—सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रहे वाद-विवाद में मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ऐसे तो हम चाहते हैं कि कई बार कहने के बाद भी यह सरकार आदिवासियों और हरिजनों की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर पाती है तो हमलोगों को सोचना पड़ता है कि अगर सरकार हमारा कल्याण नहीं करना चाहती है तो हमलोगों को आदिवासी ढंग से काम करना पड़ेगा। हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि मारकेटिंग अफसरों के स्थान रिक्त हुए और उस पर आदिवासियों ने आवेदन पत्र दिया—उन्हें रिजरवेशन के मुताबिक ७ स्थानों पर बहाल किया जाना चाहिए था लेकिन वहाँ के डाइरेक्टर ५-५ हजार रुपया घूस मांगते हैं। आप इस सम्बन्ध में जाँच कीजिए कि कितने प्रतिशत आदिवासियों की नियुक्ति इस पदों पर हुई और यदि उचित संख्या में इनको स्थान नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि पहले यह उम्मीद थी कि आदिवासी और हरिजन पर सरकार की विशेष कृपा रहती है और इस तरह आदिवासी और हरिजन काफी उन्नति किये हैं, लेकिन यह देख कर दुख होता है कि नोमिनेशन जो विधान परिषद् में हुआ उसमें राजपूत का हुआ, ब्राह्मण का हुआ, लेकिन आदिवासी का नहीं हुआ। हमें ऐसी आशा नहीं थी कि गफूर साहब के मुख्य मंत्री काल में आदिवासी एम० एल० सी० नहीं हो सकता है। खैर, जो हो गया सो हो गया। उसी तरह पांडे जी जब मुख्य मंत्री थे तो पी० सी० होरो की सीनियारिटी मान ली गई थी, परन्तु आज गफूर साहब के राज्य में पी० सी० होरो को पब्लिक सर्विस कमीशन में जुनियर बना दिया गया। ये बी० ए० आनर्स हैं और एम० ए० फर्स्ट क्लास हैं फिर भी इनको जुनियर कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी इसपर विचार करें और न्याय करें।

एक ओर सरकार ने फैसला किया कि उनकी जमीन को वापस कर दिया जायेगा। लेकिन सरकार को मालूम है कि हजारीबाग, गिरीडीह, संथाल परगना,

सिंहभूम किसी भी जगह आदिवासियों की जमीन को वापस नहीं किया गया है। बहुत से मामले हाईकोर्ट में चल रहे है। हाईकोर्ट में आदिवासी किस तरह जा सकता है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो जमीन आदिवासियों की है उस जमीन को आदिवासियों को दे देना चाहिए। सरकार को मालूम है लेकिन सरकार नहीं दे रही है। वन और माइन्स मंत्री ने कहा कि आदिवासियों को पूंजीपतियों से बचाने के लिए बीज, खाद, और धन दिये जायेंगे और उनलोगों की जमीन भी वापस कर दी जायगी। उनकी जमीन तो वापस कर दी गयी है, लेकिन उनको अभी तक बैल, खाद, बीज इत्यादि नहीं मिले हैं। हमारे आदिवासी भाई बहुत ही गरीब हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है अंत: उनलोगों के लिए फौरन इन सब चीजों क इन्तजाम किया जाना चाहियं। आदिवासी के कल्याण का सारा काम सिर्फ कागज ही पर हो रहा है।

दूसरी बात, अभी-अभी हमारे राजस्व मंत्री ने हमलोगों को नोटिस दी है।क जमशेदपुर में आदिवासियों के द्वारा टाटा कम्पनी की जमीन वह दखल कर रहे है। आपको सुन कर आश्चय होगा कि आदिवासियों ने जहां-जहां अपना मकान बनाया था, जैसे बिरसा नगर, जयपाल नगर, इत्यादि वहां के आदिवासियो को मकान से निकाला जा रहा है। उन्हें बिहार पुलिस, आर्म फोर्स और सीमा सुरक्षा दल के द्वारा निकाला जा रहा है। वह राइफल के जोर पर आदिवासियों को निकाल रहे हैं। तो मैं सरकार को कह देना चाहता हूं कि सरकार फौरन इस किस्म की कार्रवाई को रोके और उनको मकान से राइफल के बल पर निकालने का रास्ता त्याग करे, नहीं तो हम लोगों को मजबूर होकर तीर और धनुष का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री से अपील करते हैं कि आदिवासी के मकान को तोड़वाना तुरत बंद करवायें।

एक ओर आदिवासियों को उनके मकान से निकाला जा रहा है और दूसरे ओर चाईबासा में बड़े-बड़े लोगों ने गैर-कानूनी ढंग से बहुत-सी जमीन कब्जा कर ली है। उस जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और आदिवासी और गरीब लोगों ने जो होटल और दूकाने खोल रखी है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ठीकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी, साबुन बनानेवाला लाखपति पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, लेकिन जो आदिवासी हरिजन पान की दूकान पर हैं उन पर

आप ड्रास्टिक ऐक्शन तुरत ले लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसी जगह सर्किट हाउस के बगल में जो बिना परमिशन का मकान और झोपड़ियाँ बनाये गये हैं, उन पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बिना परमिशन के ये मकान बने हैं। आप सिर्फ चाईबासा, सिंहभूम के आदिवासियों पर नजर रखते हैं और हमलोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमलोगों के साथ अगर अच्छा बर्ताव नहीं किया गया तो हमलोग आपका साथ नहीं देंगे।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि २६-५-७४ को एक इन्टरव्यू हुआ जिसमें पुलिस की बहाली की बात थी, लेकिन इंडियन नेशन के विज्ञापन के अनुसार बहाली नहीं की जा रही है। इन्टरव्यू लिया गया और आवेदकों को यह कह दिया गया कि जैसे-जैसे जरूरत होगी, आप लोगों को बुलाया जायगा। सभापति महोदय, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। इन्टरव्यू के दूसरे दिन मेडिकल वगैरह हो जाना था और चौथे दिन ट्रेनिंग में भेज दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब है कि हमारे आदिवासी लोगों को नहीं लिया जायेगा और धीरे-धीरे डी० आई० जी० अपने आदमी को भरेंगे। ये बहुत ही खेद की बात है। सरकार को इस पर तुरत ध्यान देना चाहिए और उस बहाली को रोकवाना चाहिए।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंचायत राज्य क्या सिर्फ दो ही जिले में लागू होगा या और जिलों में? यदि आप दूसरे-दूसरे जिला में इसे लागू नहीं करना चाहते हैं तो छोटानागपुर और संथाल परगना से इसे तुरत हटा दी जए।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि किरिबुरू में जो एन० सी० डी० सी० का प्रोजेक्ट है, उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दूसरे-दूसरे स्टेट ऑफिसर आते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे बिहारी नौजवान को, खासकर आदिवासी और हरिजनों को बहाल नहीं करते हैं। चीफ इंजीनियर या दूसरे बड़े ऑफिसर मद्रास से आते हैं और मद्रासी बाबू को बहाल करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि बिहार के इंजीनियर या दूसरे बड़े ऑफिसर रहें, कमिटी में यहां के एम० एल० ए० रहें ताकि हमारे बिहार राज्य के लोग बहाल हो सकें।

एक दूसरी बात मैं श्री जयप्रकाश नारायणजी के बारे में कहना चाहता हूँ। वे विधान-सभा को भंग कराना चाहते हैं। मैं विधान-सभा को भंग नहीं होने दूंगा ऐसा फैसला हमारा झारखंड पार्टी ने लिया है (थपथपी । हमलोग इस विधान-सभा में पाँच साल के लिये चुन कर आये हैं, इसलिये श्री जयप्रकाश नारायण जी के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार चलेगी। जहाँ तक भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट ऑफिसर की बात है, सेठ-साहुकार और मुनाफाखोरों की बात है, उसको कुचल डालने के लिये हमलोग तैयार हैं। सरकार हमारा साथ दे। अभी हमलोगों ने चाईबासा में फैसला लिया है कि विधान-सभा भंग नहीं किया जाय और भ्रष्टाचार को मिटाया जाय। इस संदर्भ में मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि वहां के अस्पताल के बड़ा बाबू १०० रु० घूस लेता था तो बाजार में पकड़ कर हमलोगों ने घुमाया, काली स्याही पोता, डी० सी० के बाबू को पकड कर टाउन में घुमा दिया। इसके बावजूद अगर सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और ऑफिसर पर कार्रवाई नहीं करती है तो ये बड़े खेद की बात है।

मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊँ कि सन् १९७० में जब मैं मिनिस्टर था तो टाटा के गेस्ट हाउस में श्री जयप्रकाश नारायण से मेरी बातें हुई थीं। मैंने उनसे कहा था कि कभी आप जिला-दान, कभी ग्राम-दान आदि-आदि की बातें करते रहते हैं तो इससे क्या मिलनेवाला है ? हमने कहा कि २२ साल से ये सब काम आप कर रहे हैं और आपका कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सरकार भी आपको फंड देती है तो हिन्दुस्तान के किस प्रान्त, किस जिला तथा किस गांव में आपने आदर्श का काम किया है ? मैंने उन्हें बतलाया कि अगर कोई आदर्श आप किसी गांव में दिखला दें तो आदिवासी सबसे पहले इस काम को करने का फैसला करेंगे। मैंने उनसे यह भी कहा कि आपके दान में कहां मकान मिला, कहां जमीन मिली, कहां जिला मिला और कौन-सा प्रान्त मिला ? यदि नहीं मिला है तो मैंने कहा कि मेरा ४२ एकड़ जमीन है जो बहुत अच्छी जमीन है हम दान में दे देते हैं, इसी को आदर्श बनाइए। मेरी जमीन को देख कर हमारे गांव के लोग दान देंगे, मेरे पंचायत के लोग प्रभावित होकर दान देंगे, मेरे गाँव के बगल के लोग दान देंगे। इस तरह प्रान्त और जिला के लोग भी करेंगे। एक नमूना तो आप बनाएं। प्रधान मंत्री से आप इसके बारे में कहें। मैं तैयार हूँ। लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं दिया गया। मैं तो आज कहूँगा कि संत विनोबा भावे और श्री जयप्रकाश

नारायण रेल यात्रा छोड़ दें, भाषण छोड़ दें, और हमारे गांव में हमारी जमीन पर एक आदर्श काम शुरू करें।

सभापति महोदय, जयप्रकाश जी कहते हैं कि बिना पार्टी का गवर्नमेंट बनाया जाय, एसेम्बली को भंग किया जाय, परन्तु इसमें किसी का विश्वास नहीं है। अभी भी जयप्रकाश बाबू हैं, मेरी बातें उनसे हुई या नहीं, आप पूछ सकते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आखिर जयप्रकाश जी इस बुढ़ापे में क्या चाहते हैं? एक स्टूडेन्ट ने फोन पर मुझे धमकी दी कि आपको दुरुस्त कर दिया जायेगा, क्योंकि आप इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि हमलोग श्री जयप्रकाशजी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं (थपथपी)। मैं कहूंगा कि आप जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रपति बना दें, ऐसा करने ही से वे चुप रह सकते हैं। हम उनके अधीन काम कर चुके हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। आज उनका दिमाग खराब हो गया है (हंसी)। सभापति महोदय, यदि जयप्रकाश नारायण जी, ईमानदार हैं और ईमानदारी से बात करते हैं तो मैं भी कम ईमानदार नहीं हूं। आप उनसे जा कर पूछें कि बागुन सुम्बरुई से उनकी बातें जमशेदपुर में हुई है या नहीं। मैं गलत नहीं कहता हूं।

श्रीमती शहीदुन्निसा—सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मोहतरम चन्द्रशेखर सिंह के तरमीम का मैं ताईद करती हूं। हमारा रामगढ़ हल्का बिहार का एक औद्योगिक इलाका है। जहां पतरातू थरमल पावर स्टेशन, कोयले की लगभग बारह बड़ी-बड़ी खादान हैं और गिलास कम्पनियां हैं। करनपुरा कोयला खादान में तकरीबन ५ हजार मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा देहाती इलाके के खेत मजदूर, गरीब किसान और बीड़ी मजदूर आज महंगी, अभाव और बेकारी का शिकार है। इन्हें सस्ते गल्ले की दूकानों से राशन देने का इन्तजाम किया जाना चाहिये। साबुन, तेल, डालडा, चीनी सभी चीजें बाजारों से गायब हैं। कंट्रोल के मोटे कपड़े किसी को नहीं मिलते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि सरकार इसका पूरा इन्तजाम मोकम्मल तौर पर खुद करे। पतरातू साहकोल के १० हजार आबादी को पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। लोग पानी के बगैर तड़पते हैं। मेरे चुनाव के वक्त कांग्रेसी नेताओं ने वहां की जनता को पानी के इन्तजाम का वादा किया था। पाइप बिछाकर पानी का नहर बहाया गया लेकिन चुनाव के बाद सभी पाइप का पानी सूख गया। जनता फिर प्यासी ही रह गयी। सभापति महोदय, हमारे इलाका में सिंचाई के वास्ते

कोई इन्तजाम नहीं है। किसानों की फसलें सूख जाती हैं। इस इलाका में सरकारी नलकूप का इन्तजाम होना चाहिए। लघु सिंचाई से बनाये गये डैम और आहर बेकार हैं। खेती की सिंचाई नहीं हो पाती है। किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। मगर सरकारी अफसरों और ठीकेदारों को इससे फायदा पहुंचता है। हरिजन और आदिवासी मुहल्ले में चांपा कल का इन्तजाम किया जाय। जयन्ती ग्राम में अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है। जंगल के इलाका में सरकार की काफी जमीन परती पड़ी हुई है। इस जमीन को गरीब किसानों, भूमिहीनों और हरिजनों, आदिवासियों मे सरकार बांटे। सभापति महोदय, आखिर में मैं मौजूदा आन्दोलन पर दो शब्द अर्ज कर देना वाजिब समझती हूँ। आज सूबे के सरमायादार, बड़े भू-स्वामी, चोर-बाजार और मुनाफाखोर छात्र-आन्दोलन के नाम पर ज्यादती कर रहे हैं। इनकी इस ज्यादती पर रोक लगाना होगा और जमहुरियत की हिफाजत करनी होगी। गरीबों के अधिकारों को छीन कर जयप्रकाश जी मोटे लोगों तथा भ्रष्ट अफसरों के फायदों में विधानसभा को भंग करने की मांग करते हैं। बहुमत जनता इस मांग को ठुकरा चुकी है। उनके फासिस्ट इरादे को समझ चुकी है। अत: मैं सरकार से मांग करती हूँ कि फासिस्ट शक्ति को परसिस्ट करने के लिये अपनी गलत नीतियों में जल्द सुधार करे और गरीब जनता को राहत पहुँचाये।

*श्री रामसेवक सिंह—सभापति महोदय, आज पूरे बिहार में नारा लगा हुआ है—भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। सरकार भी कहती है भ्रष्टाचार, अफसर भी कहते हैं भ्रष्टाचार, कालाबाजार वाले भी कहते हैं भ्रष्टाचार, हमलोग भी कहते हैं भ्रष्टाचार, आखिर है कहाँ भ्रष्टाचार ? भ्रष्ट अगर मंत्री महोदय लोग नहीं हैं, अफसर लोग नहीं हैं, काला बाजार करने वाले लोग नहीं हैं तो क्या हमलोग भ्रष्ट हैं ? भ्रष्टाचार के बारे में हमारे सभी माननीय मंत्री एवं सदस्य जानते हैं। दारोगा बाबू तो अधिक जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहां है, कैसे है, कहाँ से आया और कहां जायेगा। श्री केदार पाण्डेय को भी इसकी जानकारी अच्छी तरह है। एक भ्रष्ट अफसर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया, लेकिन जब यह बात मंत्री जी के पास आयी तो उस भ्रष्ट अफसर को छोड़ दिया गया। यही नहीं हुआ भभुआ में पुलिस को रेड हैण्डेड पकड़ लिया गया और सरकार के यहाँ जब यह मामला आया तो उसे छोड़ दिया गया। तो कौन भ्रष्ट है ? और इस भ्रष्ट का नतीजा यह हो रहा

है कि आज जब हमलोग घर से चलते हैं तो हमसे कैफियत पूछा जाता है। हम लोग कहां घेरे जायेंगे यह पता नहीं है, पता नहीं है कि हम पटना पहुँचेंगे या नहीं। चोरी ये लोग करेंगे और पिटायेंगे हमलोग। गल्ती ये लोग करेंगे और उसकी सजा हमलोगों को मिले। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम-से-कम उन अफसरों पर ध्यान दें जो जुल्म कर रहे हैं, दिन दहाड़े डकैतियाँ कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि २७ वर्षों से कहा जा रहा है कि सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन अभी तक तिलौथू मेला बाजार का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सका है क्योंकि जयप्रकाश बाबू के दोस्त उस बाजार के मालिक हैं। ११ तारीख को खुरसीद मियां की दूकान को दिन-दहाड़े जला दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि विधान-सभा को भंग नहीं करना चाहिए और विधायकों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा गुनाह था जिसके चलते श्री विपिन बिहारी सिन्हा ने उनकी दूकान को जलवा दिया। इसलिये मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूँ कि तिलौथू मेला बाजार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। पांडे जी इसके प्रभारी मंत्री हैं इसलिये इसमें देर नहीं होनी चाहिए।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

चुटिया में एक साहू जैन कम्पनी है जहां ५०० मजदूरों को छांट दिया गया है। मंहगाई इतनी है कि १०० रुपये मन चावल हो गया है और ९० रुपये गेहूँ हो गया है। आज चारो ओर हाहाकार मचा हुआ है। आज दाने-दाने के लिये लोग तरस रहे हैं। ऐसी विषम स्थिति में इन मजदूरों की छंटनी करना कहां तक उचित है? कम्पनी के मालिक का कहना है कि बिहार सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी और हम और भी कर्मचारियों को छांट देंगे। ये लोग हमको कहते हैं कि इस्तीफा दीजिये। हमने उनसे कहा कि गफूर साहब, मुख्य मंत्री से हम कहेंगे, श्रम मंत्री से कहेंगे, यदि वे लोग नहीं सुनेंगे तो सरकार को भंग करेंगे-यही हमने कहा है। अत: मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की छटनी की गयी है उन लोगों को जल्द-से-जल्द रखवा दें, नहीं तो बहुत बड़ा विस्फोट होने की आशंका है। यह हमारा भाषण नहीं है, यह हमारी मांग है। हम शोषित दल के हैं और हम शोषित हैं।

आखिर में एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम शोषित वर्ग के हैं और सब इसका नाम लेते हैं, लेकिन खेद के साथ यह कहना होता है कि नौंहट्टा और रोहतास की जनता की चिकित्सा के लिये वहां एक भी अस्पताल नहीं है। हो सकता है जंगली इलाका है इसलिये कोई प्रबंध नहीं है या हमलोग शोषित वालों के विधायक हैं इसलिये इलाज के लिये कोई प्रबंध नहीं है। आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वहां के लिये एक अस्पताल और डाक्टर की व्यवस्था अवश्य कर। यह भी कीजिये कि इस आंदोलन को बन्द किया जाय चूंकि २ तारीख से द्वार पर ही होने को है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—उपाध्यक्ष महोदय, इस बार के राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिनों तक जो यहां बातें हुई हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज विधान सभा के विघटन के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से कहा कि सरकारी बेंच का काम बहुत हल्का हो गया है।

*श्री चन्द्रशेखर सिंह—नहीं, भारी हो गया है।

उपाध्यक्ष—शांति, शान्ति। जवाबदेही भारी हो गयी है और जवाब हल्का हो गया है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—यहां जो दो-चार बातें कही गयीं हैं मैं पहले उन पर कहूँगा। श्री भोला प्रसाद सिंह ने शुरू में कहा है कि १३ करोड़ रुपया ला एन्ड आर्डर के ऊपर खर्च हो गया है। अभी कल ही इसी तरह के प्रश्न को अध्यक्ष महोदय ने अतारांकित कर दिया है। कुछ हुआ है वह आवश्यक है। लेकिन १३ करोड़ बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो माननीय चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि फारबिसगंज में केन्द्र की सहायता से फारम खुलने वाला है उसको यहां से जाने देने के लिये हम सहमत हो गये हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक्वीजीशन से दस हजार एकड़ जमीन लेनी होगी। ८ लाख के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने बातें उठायी हैं। गृह मंत्री श्री दीक्षित जी आये थे। बिहार में जहां पूरा खर्च नहीं होता था, फोर्थ फाईव ईयर प्लान के लास्ट दो वर्षों में हरेक आईटम में एचीवमेन्ट हुआ है। बिहार में पहले उनका रुपया जितना खर्च नहीं हो पाता था, उसमें अब एचीवमेन्ट हुआ हैं। गत साल १३३ करोड़ रुपया का प्लान था और भारत सरकार द्वारा उसमें १० परसेन्ट कट करने का था, उसको छोड़कर हमलोगों ने उसे पाई

पाई कर पूरा कर दिया। अभी भी मैं कहता हूं कि सभी कठिनाइयों के बावजूद भी हमलोग अपने प्लान को पूरा करेंगे और एक पैसा भी सरेन्डर नहीं किया है और न करेंगे। गांवों के विकास के लिये १२-१३ करोड़ की योजना है जिसमें से २-३ करोड़ की योजना गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने तथा बिजलीकरण आदि के लिये है। इस योजना में हमलोगों ने बहुत बड़ा एलोकेशन किया है और इसी से मुझे बिहार की गरीबी दूर करने का मौका मिलेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी दूर करने का जो सवाल है, वह तो तुरत नहीं हो जायेगा, धीरे-धीरे ही होगा और हम इस काम को पूरा करेंगे। एक बात सेन्ट्रल असिस्टेन्ट की कही गयी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब उसकी क्राइटेरिया बदल गयी है। अब ६० परसेन्ट पापुलेशन के आधार पर मिलता है, १० परसेन्ट मेजर इरिगेशन, १० परसेन्ट स्पेशल प्रोवलम पर जैसे, बाढ़ आदि पर। हम ट्राइवल एरिया में ज्यादा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बात उठायी गयी है कि बैंक के राष्ट्रीयकरण करने से डिपोजिट में कमी हुई है, यह सही है। इस प्रोबलम को हमलोगों ने दो साल पहले प्रधान मंत्री के सामने जोनल कौंसिल में उठाया था। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नेशलाइजेशन के पहले जहां ८० करोड़ रूपया खर्च करते थे आज २०० करोड़ रूपया खर्च करते हैं। पहले दो लाख को आबादी पर बैंक का एक ब्रांच था और अब हर ब्लॉक में हम बैंक की शाखा खोलना चाहते हैं। १९७४ के बाद ५०० ब्लॉक में बैंक की शाखा खुल जायेगी और अब २ लाख के पापुलेशन के बदले ८० हजार के ही पौपुलेशन पर हम बैंक की शाखा खोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ये दो बातें सदन की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में ५०० ब्लॉकों में बैंक की शाखायें खोली गयी है और हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में जहां बैंक है वहां ट्रेजरी खुलवाकर लोगों की असुविधा को दूर करें। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में जहां बैंक की शाखा होंगी वहां ट्रेजरी भी खुलेगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है लैंड रिफौर्म के बारे में। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता हूं—१९७३ साल को लैंड रिफौर्म ईयर घोषित किया गया था उस दरम्यान में लैंड सिलिंग, बटाईदारी, भूदान तथा होम स्टीड लैंड के बारे में काफी प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जिस हद तक होना चाहिये था नहीं

हुआ है। फिर भी हम चाहते हैं कि जो काम पूरा नहीं हुआ है उसको पूरा करने के लिये सेकेन्ड फेज में १९७४ में इस काम को शुरु करके जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक छोटानागपुर के भाइयों ने वहां के संबंध में बहुत से सवाल उठाये हैं—छोटानागपुर की गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिये वहां ओटोनो स बोर्ड की स्थापना की गयी है और अभी हाल में सरकार ने फैसला किया है कि वहां के आउट साईड प्लान के लिये जो रुपये दिये गए हैं उसकी स्वीकृति प्राधिकार स्वयं करेगी। अभी हाल ही में बहुत से अमेंडमेंट हुये हैं जिसमें उनलोगों के सभी सुझावों को मान लिया गया है कि जितने भी कार्य वहां के लिये किये जायेंगे और लोकल इम्पोर्टेन्स का होगा, छोटानागपुर और संथालपरगना में उसकी स्वीकृति प्राधिकार ही देगी। छोटानागपुर और संथालपरगना के भाइयों की सुविधा को नजर में रखते हुये हमने रांची में हाईकोर्ट का एक बेंच कायम कर दिया है। लेकिन बहुत से केस फाईल करने के लिये वहां क लोगों को अभी भी पटना आना पड़ता है। अभी हाल ही में मैं जब प्राधिकार की बैठक में रांची गया था तो वहां इसकी जानकारी मिली और अब हम वहां एक रजिस्ट्रार का पोस्ट कायम करने जा रहे हैं ताकि जो भी केस फाइल करना होगा उसके लिये वहां के लोगों को पटना नहीं आना पड़ेगा और वे वहीं अपना केस फाइल करेंगे और उससे वहां के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि छोटानागपुर को ७५ प्रतिशत सबसिडी दिया गया है, इतना सबसिडी बिहार के किसी भी हिस्से में नहीं दिया गया है।

*श्री देवदत्त साहू—वहां हाईकोर्ट को परमानेन्ट बेंच क्यों नहीं बना देते हैं ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—धीरे धीरे न काम होता है। आप तो अभी नये हैं आपके स्पीड में और हमारे स्पीड में कुछ अंतर है न।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (सा०)—छोटानागपुर के लोगों की जमीन के रेस्टोरेशन के लियं सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—आदिवासियों का जहां तक फीगर हमारे पास है ६ हजार केसेज रेस्टोरेशन के थे और सब का रेस्टोरेशन का आर्डर हो गया है।

श्री देवदत्त साहू—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी सरकार से चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने पर्चा दिया था कि ताना भगत की जो जमीन है उसपर उनको कब्जा मिल जायेगा लेकिन अब तक नहीं मिला है कब तक मिलेगा।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मंत्री महोदय कह रहे हैं कि लैंड रिफार्म का काम हुआ लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक हरिजन आदिवासियों को नौकरी में, सर्विसेज में, रिप्रेजेन्टेशन का सवाल माननीय सदस्यों ने उठाया है, उसके संबंध में कहना है कि मुख्य मंत्री के अन्दर में एक सेल, हरिजन, आदिवासी और माईनोरीटी लोगों के लिये बनाया गया है ताकि उनको रीक्रूटमेंट में रिप्रेजेन्टेशन मिल सके, परमोशन में मिल सके। इसलिये जो एक्जामीनेशन प्रोमोशन के समय हुआ करता था, उसको उनलोगों के लिये हटा दिया गया है। जब से नए मुख्य मंत्री जी आए हैं, हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने की जितनी चिंता इनको है, बहुत कम लोगों को होगी। जितने अफसरों को इतने कम समय में ससपेन्ड किया, बड़े-से-बड़े लोगों को भी इन्होंने ससपेन्ड किया, कभी का इतिहास नहीं होगा कि इसका फ्रैक्शन भी हुआ होगा।

श्री जनार्दन तिवारी—श्री रामचन्द्र सिन्हा, पी० सी० भगत और बी० पी० कश्यप को क्यों बचा रहे हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—आपका सहयोग मिलेगा तो एक भी बड़ी मछली इनके जाल से नहीं निकलेगी। आपने देखा कि काफी अफसरों को इन्होंने ससपेन्ड किया, आई० ए० एस० रैंक के अफसरों को भी इन्होंने ससपेन्ड किया।

*श्री रामशरण सिंह—वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक क्षमता बढ़ी है तो क्या भौतिक आय प्राप्त करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है ?

श्री दारोगा प्रसाद राय परफोरमेन्स बजट एक-दो विभाग का आया है उसको देखेंगे तो फीजिकल टारगेट देखने का मौका मिलेगा।

श्री जय नारायण—अवकाश-प्राप्त अधिकारियों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी गयी हैं उन्हें भी क्यों नहीं कहते ?

(जवाब नहीं दिया गया)

श्री दारोगा प्रसाद राय—इन्दिरा ब्रिग्रेड के संबंध में बातें कही गयी हैं। इसका जवाब कल मैं कौल अटेनशन का जवाब देने वाला हूँ, उसी में दे दूंगा।

एक बात आयी है कि जेल से कैदी विद्यार्थियों को रेवेन्यू बिल्डिंग पर ले आया गया, यह ठीक नहीं मालूम होता है लेकिन जयप्रकाश जी का समाज में आदर है, उनका समाज में एक स्थान है....

साम्यवादी दल की ओर से आवाज—आप लोगों के दिल में भी उनके लिए यही भावना है :

श्री दारोगा प्रसाद राय—उन्होंने बहुत जोर लगाया था और कहा था कि हमारे विद्यार्थी जेल में हैं, इसलिए उनको दिखाने के लिए हम अपना प्रदर्शन जेल की तरफ से ले जायेंगे तो जेल में काफी लोग हैं। बीच-बिचाव करके ऐसा किया गया। इसका कोई खास अर्थ नहीं है। प्रैक्टिकल विचार से ऐसा किया गया कि विद्यार्थी लोग जुलूस देख लें। वहाँ केवल ७ ही विद्यार्थी गए थे।

एक बात उठायी गयी है, और बराबर उठायी जाती है, सर्चलाइट और प्रदीप के डीलिस्टिंग की। तो यह बात हुई है। यह किसी डेमोक्रेटिक सरकार के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कभी-कभी मजबूरी भी होती है। मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि, यहाँ के प्रेस को जो फ्रीडम मिला वह शायद इंग्लैंड, अमेरिका से भी ज्यादा है, लेकिन मुझे माफ करेंगे, इधर ३ महीने में मैंने देखा, मुझे भी १२ वर्षों का अनुभव है, जवाहर लाल जी के खिलाफ किसी इग्गी-दुग्गी का स्टेटमेंट गया तो वह पहले पेज में छपा और जवाहर लाल जी का कोई स्टेटमेंट हुआ तो वह ९वें पेज पर छपा। तो आजादी का यह माने नहीं होता है। यह आजादी सिलोन में भी नहीं है। जब यहाँ छात्र आन्दोलन कहीं नहीं था तो...

उपाध्यक्ष—कन्ट्राडिक्शन भेजिए तो उसे भी कभी-कभी नही छापता है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—प्रेस के फ्रीडम का इस तरह से दुरूपयोग दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ।

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल—किसी प्रेस के बारे में यह कहना ठीक नहीं है। हमारी सरकार ने भी किसी प्रेस के साथ ऐसा नहीं किया था। यह डिमोक्रेटिक तरीका नहीं है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या हमारी सरकार ने किसी प्रेस में ताला बन्द किया या किसी प्रेस को लूटा है ?

श्री जय नारायण—सरकार ने कहा कि बिजनेस हाउस का कंट्रैक्ट है प्रेस के साथ । तो क्या उसको खतम करना चाहते हैं ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—वही कहना चाहता हूं । लंका की सरकार ने क्या किया । भारत सरकार सोच ही रही थी लेकिन लंका की सरकार ने सारे अखबारों को बिजनेस हाउस से डिलिंक किया । किसी प्रेस को फ्रीडम हो सकती है, लेकिन वह बिजनेस हाउस की बुलेटिन नहीं हो सकती है । जनता को यह फैसला करना है कि कौन सच है, कौन झूठ है ।

श्री भोला प्रसाद सिंह—श्री दारोगा प्रसाद राय जी का जो भाषण हो रहा है प्रेस के बारे में वह भारतीय संविधान का उल्लंघन है जिसका शपथ खाया है । वह छींकते हैं या खाते हैं वह सभी अखबारों में निकलता है । तो कैसे कहते हैं कि उनकी बातों को छापा नहीं गया ? फ्रीडम आफ प्रेस की संविधान में गारंटी है ।

उपाध्यक्ष—यह संविधान के उल्लंघन की बात नहीं है ।

श्री भोला प्रसाद सिंह—सर्चलाईट प्रेस के बारे में वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके विरोध मे हमलोग सदन का त्याग करते हैं । (श्री भोला प्र० सिंह सहित कुछ सदस्य सदन का त्याग किये)

श्री दारोगा प्रसाद राय—अगर सरकार समझती है कि हमारी एस्टेब्लिशड पालिसी कोई डिटरमाइंड होकर उसके ट्रूथ को सप्रेस करने में लगा हुआ है तो उसने उस प्रेस को फैसिलिटी देना छोड़ दिया । क्या सर्चलाईट का इसमें कोई लिगल राईट हैं ? तो मैं यह शुरू से कह रहा था । मैं उसके खिलाफ नहीं कह रहा हूं । आजादी जरूर मिली हुई है प्रेस को । लेकिन वह तो अरबपतियों का अखबार है वे चलावें । हम तालाबन्दी नहीं कर रहे हैं, हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं । जब आपको अधिकार है कि जो मन आवे लिखिये तो हमको भी अधिकार है हम जिसको चाहें उसको एडभर्टिजमेंट दें ।

*श्री रामजी प्रसाद सिंह—आपको यह राइट नहीं है कि जिसको मन में आवे उसे ही दीजिये ।

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल—यह गलत बात है।

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—मेरा प्वायंट औफ औडर है। मैं दारोगा बाबू की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि बिहार की जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। डिस्टींगशन पेपर में किया जायेगा तो क्या इंडियन नेशन और आर्यावर्त्त उससे बेटर हैं। उसने एडीटोरियल में लिखा है कि छात्र आंदोलन चलावें। इंडियन नेशन के एडीटोरियल को देखिये।

श्री दारोगा प्रसाद राय—इस पर विचार हो सकता है। लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम औफ स्पीच और फ्रीडम औफ सब चीज हो इसी संदर्भ में मुझे एक अच्छी कहानी याद आ गयी। लदन की सड़क पर एक अंग्रेज छड़ी घुमाते हुए टहल रहा था। वह छड़ी दूसरे सज्जन की नाक पर लग गयी। तब उसने कहा कि यह पब्लिक रोड़ है और दूसरे लोग भी टहलते है, इसलिये जरा देखकर छड़ी घुमाइये। तब छड़ी घुमानेवाले ने कहा कि 'This is public road, I have every right to move on this road and move stick." तब उसने कहा कि—"Well, but where your right ends, my nose begins." आप छड़ी इधर-उधर देखकर घुमाइये।

इसलिये यह कोई पहली दफा हिन्दुस्तान में नहीं हुआ है। बहुत से अखबार दूसरे प्रान्त में डिलिस्ट हुए हैं। यह आपका विचार हो सकता है कि बड़ा अनर्थ हो गया है। लेकिन ट्रेजरी बेंच पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी कर्त्तव्य हो जाता है कि सरमायादारों के और मुट्ठी भर पूंजीपतियों के जोर को रोकें और गरीबों को पनपने दें।

*श्री रघुनाथ झा—हम जानना चाहते हैं कि बिहार रिलीफ कमिटी पर इंक्वायरी बैठाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—गुजरात के बाद ऐसा लगा कि एक नई लहर आ गयी है। माननीय सदस्यों को भ्रम नहीं है, लकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, जैसे माननीय सदस्य श्री जयनारायण ने कहा, श्री अनुरुद्ध झा ने कहा, और मंडल जी ने तो ए वन कहा। यह मंडल जी का हिस्टोरिक स्पीच था। उन्होंने ट्रूथ को फियरलेसली कहा। बिहार की जनता को सरकार की तरफ से थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। यह मामूली खेल नहीं है। थोड़े से

विद्यार्थी आवें और कहें कि हम आंदोलनकारी हैं, आप इस्तीफा दीजिये तो हमारे लिये यह संभव नहीं है।

चीन का आक्रमण हुआ तो जवाहर लाल जी को उसमें असफलता मिली तो कुछ लोगों ने आक्रोश प्रकट किया, लेकिन वे जनता के बहुत ही प्रिय थे नतीजा यह हुआ कि बाद में जिन लोगों ने आक्रोश प्रकट किया था वे वास्तविकता को समझे। आज बाढ़ के कारण या सुखाड़ के कारण या बगला देश के कारण मंहगाई आयी। इसको मैं मानता हूँ कि मंहगाई है। हमने १९७०-७१ से ही अनाज मंगाना छोड़ दिया। आप हमारी इस कमजोरी को समझकर यह सोच लें कि अब मान लिया तो यह आपकी भूल है। आप उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में देखा कि क्या हुआ। आपने यह भी देखा कि श्री सुब्बा राव, अपने पद से रिजाइन करके प्रेसिडेन्ट के पद के लिये खड़ा हुए उसका क्या नतीजा हुआ। फिर आपने देखा कि अतुल्यघोष, मुरारजी देसाई खड़ा हुए और उन्हे असफलता मिली। यह छात्र आन्दोलन नहीं है। अगर यह छात्र की मांग विधान सभा भंग करने की होती तो समझ में आ सकती है, लेकिन अगर यह सवाल पूछा जाता है तो वे भाग जाते हैं। इसमें दो राय नहीं हैं कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मंहगाई सब है और इसमें दो राय नहीं हो सकती है। मैं श्री जयप्रकाश बाबू से कहूँगा कि सिर्फ तीन महीना वे इसे स्थगित रखें। अगस्त के बाद उनके इस आन्दोलन में हमलोग भी साथ देंगे।

बेरोजगारी मिटाना मुश्किल नहीं है। अगस्त महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होनेवाला है। ये चाहते हैं इसके पहले सभी विधान-सभा को विघटन कराके अपने मन के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव करा लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है उसका क्या अन्जाम हुआ यह सभी को मालूम है। ये चाहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में अपने आदमी चुनकर एक दिन में संविधान को बदलेंगे और अपने मन के अनुसार काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगस्त भर इस आन्दोलन को छोड़ दीजिये और उसके बाद तीनों समस्याओं-भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मंहगी-इन तीनों समस्याओं के साथ हमलोग एक साथ होकर जूझेंगे। आज जयप्रकाश जी और छात्रों का आन्दोलन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें किन लोगों का हाथ है। हमलोग जानते हैं कि गांधी जी का आन्दोलन इसलिये सफल हुआ था कि उनका अहिंसा का रास्ता था। आज मूर्तिजी, सत्य-मूर्तिजी बेग लटकाकर घूमते हैं और किस तरह से रुपया वसूल करते हैं और इसके

बाद भी सत्य, अहिंसा और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। आज सारे ठीकेदार और पूँजीपति सन्त हो गये हैं। बिहार के रिलीफ कमिटी, भूदान कमिटी और खादी ग्रामोद्योग संघ में काम करने वाले लोग २०० रुपया से लेकर ७०० रुपया तक पाते हैं और सत्याग्रह भी कर रहे हैं। इसमें सरकार का भी पैसा खर्च होता है।

श्री रघुनाथ झा—सरकार जब रुपया देती है तो इसका आडिट क्यों नहीं कराती है? मैं चाहता हूँ कि इसके लिये हाउस के सदस्यों की एक कमिटी बनायी जाय। हाउस की कमिटी होनी चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र—जब सरकार जानती है कि वे सरकारी पैसे से माल उड़ाते हैं और सरकार ऑडिट नहीं कराती है तो इसके लिये सरकार कसूरवार है।

(सदन में शोरगुल)

*श्री अब्दुल गफूर—उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज सदन में एक नयी बात पैदा हुई।

श्री विद्याकर कवि—मेरी नियमापत्ति है। यह गम्भीर बात है कि सदन में कोई बैठे-बैठे कुछ ऐसी बात कहे जो आपत्तिजनक हो। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को चलाने का दो तरीका है, एक तो विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम के मोताबिक कार्य चलाया जाता है और दूसरा परम्परा के अनुसार चलाया जाता है। आप विधान-सभा नियमावली के नियम-६ के खंड-५ को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य मंत्री या अन्य किसी मंत्री को विमर्श के अन्त में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा, चाहे वे विमर्श में पहले भाग ले चुके हों या नहीं, और अध्यक्ष यह पूछ सकेंगे कि इस भाषण के लिये कितना समय अपेक्षित होगा ताकि वे विमर्श की समाप्ति का समय नियत कर सकें। तो यह वित्त मंत्री का समय था और वित्त मंत्री ने पूरा समय लिया और अब मुख्य मंत्री बोलने के लिये खड़े हुए हैं। मेरा कहना है कि वित्त मंत्री ही भाषण करते रहते, (उनका भाषण भी आवश्यक था) तो ठीक था। यह परिपाटी है कि अगर कोई वित्त मंत्री बोल रहे हैं और किसी सम्बन्धित विभाग की बात आ गयी तो सम्बन्धित विभाग के मंत्री बीच में हस्तक्षेप करके कुछ बोलते तो एक बात थी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दो-तिहाई समय ले लिया और अब मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं इसी पर मेरी नियमापत्ति है।

उपाध्यक्ष—प्रिसिडेन्ट यही रहा है कि सुधांशु जी के टाइम में भी पाँच-पाँच, सात-सात मिनिस्टर बोलते थे और अन्त में मुख्य मंत्री श्री के० बी० सहाय बोलकर बैठ जाते थे। यह तो परम्परा रही है, आप प्रोसिडिंग मंगा कर देख लीजिए।

श्री अब्दुल गफूर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लूँगा लेकिन बहुत मोखतसर में मैं अपनी उन भावनाओं को आपके समक्ष जिक्र करना चाहता हूँ, जो मेरे लिये, सदन के लिये, एक नयी चीज होगी। हमारे दोस्त श्री भोला प्रसाद जी बोल रहे थे तो वे बोलते चले गये। वे सोचते हैं और अच्छा-अच्छी चीज सोचते हैं और अच्छा बोलते हैं लेकिन वे बोलते हुए कभी ऐसी गन्दी बात रख देते हैं जिससे उनका इन्टेन्शन दब जाता है। श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल जी बैठे हुए हैं। इसलिये मैं कह रहा हूँ क्योंकि वे कह रहे थे कि बिहार से सारा ओपोजिशन पोलिटिकली गायब हो गया है। मनुष्य के जीवन में कभी-कभी दिल और दिमाग में टक्कर होता है। जयप्रकाश जी नेता हैं, हो सकता है कि उनके नेता कोई दूसरे हों। सूबे बिहार में नहीं, दूसरी जगह हों। जहांतक विधान-सभा का तालुक है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी के दिल और दिमाग में टक्कर था, क्या टक्कर था? हम सभी पोलिटिकल पार्टी ने मिल कर हिन्दुस्तान को आजाद कराया और आजाद इसलिये कराया कि बालिग मताधिकार के जरिये सरकार बने और इसीका नतीजा है कि ३१८ का यह हाउस है और हम और आप आये हैं। ३१८ में से २० इस्तीफा देकर चले गये और इतने लोग बचे हुए हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरे पोलिटिकल पार्टी के नेता दिल्ली से बोलते हैं, क्या वे भत्ता नहीं लेते हैं? वेतन और भत्ता लेने की बात कहने में उनको शर्म आनी चाहिए, क्या देशमुख साहब हवाई जहाज से यहां नहीं आते हैं और वे किसी तरह का भत्ता नहीं लेते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर पोलिटिकल पार्टी को यह फैसला करना चाहिए था कि यहां पर जमहूरियत रहे या नहीं। मैं जयप्रकाश जी और नाना देशमुख का आदर करता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने एक खत लिखा जिसको जयप्रकाश बाबू की बेगम ने उनको ले जाकर दिया। मैं उनकी तारीफ करूँगा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में अच्छा रोल किया। आजादी की लड़ाई में उन्होंने जो रोल अदा किया वह इतिहास में गोल्डेन हरफों में लिखा जायेगा। लेकिन अभी जो वे रोल अदा कर रहे हैं, उससे उन्होंने अपनी सारी

कमाई को धो दिया। विनोबा जी में हिम्मत है जो उनसे कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं तो एक अदना आदमी हूँ और मैं उनसे क्या कहूँ ? लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वे अपना आन्दोलन वापस ले लें। कुछ दिन पहले ऐसी खबर छपी थी कि मैं उनको ऐरेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि वे इसके पहले भेलोर में रहे चिकित्सा के लिये, इसलिये मुझे उनके स्वास्थ्य की चिन्ता है।

मैं कहूँगा कि सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता ने एक ज्योतिषी से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि दो बजकर दस मिनट पर यदि आप इस्तीफा देंगे तो बहुत जल्द पावर आपके हाथ में आ जायेगा, इसलिये दो बजकर दस मिनट पर आकर बैठ गये। इत्तफ़ाक़ से अध्यक्ष महोदय उस समय नहीं थे। यदि रहते तो शायद ज्योतिष की बात सही हो जाती। अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति के कारण वे अपना इस्तीफा सचिव महोदय को दे दिये। वे इस चीज को भूल गये थे कि सचिव महोदय की हस्त-रेखा दूसरी है और अध्यक्ष महोदय की हस्त-रेखा दूसरी है। इस बार आपने हाउस में बैठकर जो नाम कमाया है, जितना आप आजादी की लड़ाई में नाम कमाये थे और जिस तरह का रोल आपने उस समय कमाया था, इस बार भी आपने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और बिहार की हिस्ट्री में सुनहले अक्षरों में लिखा जायेगा। "वेस्टर्न इंडिया" नामक किताब में नाम छपेगा। ये जितने लोग यहां पर इस हाउस के अन्दर बैठे हुये हैं उन सारे लोगों ने अपनी-अपनी जगह पर एक अहम रोल अदा किया है। मैंने जनसंघ को, मिलीटरी और सिवीलीयन, दो रूपों में देखा था। लेकिन हमने देख लिया किस तरह इनके विचारों में भी तफरका है। मैं चन्द्रशेखर बाबू से कहूँगा कि जब हाउस के अन्दर मैंने श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल का भाषण सुना तो उनमें मैंने गहरी तबदिली पाई है। आज वक्त आया है कि इस हाउस को यह सोचना है कि सूबे में आज की हालत में हमें क्या करना है। आप जानते है कि एक माननीय सदस्य कपिलदेव बाबू (यहाँ वे नहीं हैं, मैं उनको दाद देता हूँ) को छूरा (कमर, पीठ और गर्दन की ओर इशारा देते हुए) यहां-वहां भिड़ाया गया, लेकिन वे चुपचाप कहते हुए बैठ गए कि जो करना है करो लेकिन हम लिख कर नहीं देंगे। श्रीबाबू के समय से आप जानते हैं कपिलदेव बाबू एक पक्के इरादे के आदमी हैं और अगर वे अपने सिद्धान्त से अलग होना चाहते तो आज वे अच्छे-से-अच्छे मिनिस्टर होकर रहते, लेकिन उस वक्त भी

ये अपने सिद्धान्त में रहे। जिस वक्त छूरा का वार इनपर किया जा रहा था तो उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई और इस तरह उनकी जान बची। अगर दो-तीन मिनट के अन्दर पुलिस फोर्स वहां नहीं पहुंचती तो ये जो नाचने वाले हैं इशारे पर जो विधान-सभा को भंग करने की बात करते हैं इनकी जान ले लेते। ये इतने बड़े लीडर हैं और इनको प्रोटेक्शन समय पर नहीं मिला ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्हें कठिनाई हुई। इसकी सूचना मिली है कि आरा में आज भी १ लाख रुपया लोगों से वसूल किया गया और जयप्रकाश जी का नाम लेकर लोगों से १०-१० लाख रुपया वसूल किया जाता है। आज भी मेरे एक दोस्त ने फोन पर बताया कि किताब लेकर, जयप्रकाश बाबू का नाम लेकर चन्दा वसूल किया जा रहा है। हमारे कृष्ण बहादुर जी का फोन हमारे पास आया।

अनेक सदस्य—आप इसको बन्द करायेंगे या नहीं ?

श्री अब्दुल गफूर—तो मैं बता रहा था......

*श्री जनक यादव - हमारा प्वाएन्ट आफ आर्डर है। विधान-सभा के अनेक मेम्बरों के साथ ऐसी-ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमलोगों को बचाने के लिए आज तक सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की है ?

श्री अब्दुल गफूर—मैंने कहा था और आज भी मैं कहता हूं कि जिन लोगों को जमहुरियत में विश्वास है, आज भी हाउस में बैठे हुए हैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास हैं

श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—आपकी पार्टी की श्रीमती गायत्री देवी रात भर डाकबंगला में रही और आपके एस० पी० और कलक्टर उनके संरक्षण में नहीं रहे, लेकिन आज तक आपने उन अधिकारियों को वहां से ट्रान्सफर तक नहीं किया - इसका आप जवाब दें।

श्री अब्दुल गफूर—हमारे भोला बाबू ने जिस विषय की चर्चा की मैं व्यावहारिक चीजों को बताना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में हमलोग आज हैं। हमने तो सिर्फ एक उदाहरण रखा। आज मैं यह कहता हूं कि हमारे जो जनसंघ के मेम्बर हैं, अब वे उस हैसियत से वहां नहीं रहे, लेकिन उन्हें भी सोचना पड़ा और उनके आपस के विचार भिन्न हुए। आज अगर कोई पोलिटिकल पार्टी है जो यह कह सके, हिम्मत के साथ कह सके कि विधान-सभा का विघटन हो ? अगर विधान-

सभा का विघटन होना होगा तो वह हमारे रोकने से नहीं रुकेगा। मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूँ कि यह नहीं हो सकता है। मुव्हमेंट तो खत्म हो गया क्योंकि इस हाउस के अन्दर एक भी सदस्य नहीं हैं जो इसको चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला अटैक हुआ एक हरिजन मेम्बर पर, अगर श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल पर अटैक होता तो खून की नदी बह जाती लेकिन श्री रमई राम के साथ यह घटना घटी। कुछ मुस्लिम पर भी अटैक हुआ, किसी सूअर के गले में गफूर का नाम लिख छोड़ा गया लेकिन हमलोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि इससे घबड़ा जायें। हवन किया गया—स्वाहा किया गया, जितने तरकीब थे पौलिटिकल, रिलीजियस, सभी का इस्तेमाल किया गया।

कुछ दिन पहले जब हमलोगों की असेम्बली बन्द हो गयी थी तो विद्यार्थियों का स्टेटमेंट हुआ कि असेम्बली को बुलाया जाय। मालूम ऐसा होता था कि असेम्बली अगर नहीं बुलायी जायेगी तो सारा मुवमेंट फेल हो जायेगा। जब पिछली दफा असेम्बली खत्म की गयी तो यह कहा गया कि असेम्बली बुलाओ, लेकिन जब हमलोगों ने असेम्बली को बुलाया तो अब यह नारा दिया गया कि किसी भी सदस्य को असेम्बली ही नहीं जाने दिया जाय। हमने पहले भी कहा था कि इस आन्दोलन के पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। आज भी कह रहे हैं कि इस आन्दोलन में विद्यार्थियों का सिर्फ नाम है। यह अलग बात है कि हम लोगों की परेशानी बढ़ी है। यह परेशानी हर मुल्क में बढ़ी है, सिर्फ हमारे ही यहां नहीं है। आज उनका नारा है कि "गुजरात की जीत हमारी है अब बिहार की बारी है"। इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए कुछ पोलिटीकल पार्टी तैयार है और वे समझ रहे हैं कि आन्दोलन करने का यही राइट टाइम है। पार्टीलेस गवर्नमेंट में कुछ भी काम नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की गवर्नमेंट थी जिसके कारण पाकिस्तान को दो टुकड़े होना पड़ा। डिमोक्रैसी के रहने से ही हमलोग कुछ एक-दूसरे पर बोल सकते हैं। अगर यहां डिक्टेटरशिप रहेगी तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कम-से-कम यहां बोलने की तो पूरी आजादी है। पांच साल के बाद यहां चुनाव होगा तो उसमें कोई भी आ सकते हैं। जिस तरह की शक्ति के कारण पाकिस्तान को दो टुकड़ा होना पड़ा, उसी तरह की शक्ति का हाथ इस आन्दोलन के पीछे है और वह शक्ति हिन्दुस्तान की युनिटी को देखना नहीं चाहती है। श्री जवाहर लाल नेहरु ने एक दफा कहा था कि ३

चीजें दुनिया के हर कोने में मिलती हैं, डालडा, बाटा और एक बिरादरी के लोग हैं, जहां जाइयेगा वहीं मिलेंगे। यदि डिमोक्रेसी रहेगी तब ही कोई गांधी मैदान में १ लाख, २ लाख और १० लाख के बीच भाषण कर सकता है। लेकिन २० साल के बाद जब पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ अब दोनों जगह गाइडेड इलेक्टेड गवर्नमेंट रन कर रही है, एक तरफ भुट्टो साहेब और दूसरे तरफ मुजीब साहेब सरकार चला रहे हैं। जब तक यह जनतंत्र रहेगा तीनों जगह कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। बिहार में हर चीज के लिए ड्राइभ होता है। इस बिहार में गांधी जी ने अपना ड्राइभ किया, महात्मा बुद्ध ने भी अपना ड्राइभ इसी बिहार से किया। डिमोक्रेसी रहे या नहीं रहे, उसका भी निर्णय इसी बिहार को करना है कि यहाँ प्रजातंत्र रहे या नहीं रहे। ३१८ या ३१९ का यह हाउस है जहां ६ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक महान नेता के कहने पर इस ३१८ के हाउस से मात्र १८ या २० सदस्यों ने अपना त्याग-पत्र दिया। क्या इस पर भी इस आन्दोलन को चलानेवाले इस आन्दोलन को वापस ले लेंगे? मैं उनकी इज्जत करता हूं। अब भी इस आन्दोलन के संचालकों को मैं इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि वह रिकन्सीडर करके बतलायें कि वे इस सूबे में क्या चाहते हैं? इसके लिए वे हमें सहयोग दें। हम दोनों हाथ फैलाकर उनका सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। लाखों, करोड़ों लोगों के मरने के बाद यह चीज हमें मिली है, इसे कोई छीनने न पावे।

कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा है कि जयप्रकाश बाबू का कहना है कि श्री लल्लू प्रसाद यादव एवं श्री सुशील कुमार मोदी की सिफारिश पर चुनाव के लिये टिकट दिया जायगा तो यह कुछ अजीब बात मालूम पड़ती है। कपिलदेव बाबू से जो मेरी बातें हुई है उसे मैं विस्तृत रूप से यहां कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि मैंने उन्हें कहा था कि आप भावुक आदमी हैं; भावुकता में आप इस्तीफा मत दीजियेगा। इस पर उन्होंने जबाब दिया कि मैं इस्तीफा इसलिये देना चाहता हूं कि यह जो जनतंत्र के लिये चुनौती दी गयी है उसका मुकाबला मैं इस्तीफा देने के बाद कर सकूंगा। यदि कपिलदेव बाबू इस्तीफा भी दे देंगे तो मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और मैं विश्वास करता हूं कि सदन में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों की ओर से, उनके खिलाफ कोई आदमी खड़ा नहीं किया जायेगा। ९९ प्रतिशत लोग विधान-सभा विघटन के खिलाफ हैं

और ६० प्रतिशत छात्र भी इसके खिलाफ हैं। सिर्फ आर० एस० एस० के लोग असेम्बली भंग की बात करते हैं। छात्रों से इस सिलसिले में मेरी बातें हुईं और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश बाबू की हस्ती ही क्या है? उनके पास तो १००-२०० भूदान के लोग हैं। इस क्रम में जो श्री चन्द्रशेखर सिंह, श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल एवं श्री भोला प्रसाद सिंह ने भाषण दिया है, उसके लिये मैं अपनी ओर से अपने तमाम दोस्तों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इस अवसर पर अपनी जिम्मेदारी को समझा है और अपनी अक्ल से फैसला किया है। इसके लिये आप को ही क्रेडिट है। हमारे ऐसे मुख्य मंत्री कितने आयेंगे और जायेंगे लेकिन यह क्रेडिट की जिम्मेदारी अगर सबसे ज्यादा है तो आप लोगों को है।

*श्री चन्द्रशेखर सिंह (कम्युनिस्ट)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जयप्रकाश जी ने बांकीपुर मैदान में सभी विधायकों के बारे में यह बयान दिया है कि सभी विधायक भ्रष्ट हैं। उन्होंने किसी खास विधायक के बारे में नहीं कहा है बल्कि सभी विधायकों पर यह आरोप लगाया है। उनके मुंह से इस तरह का स्टेटमेंट बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि जयप्रकाश बाबू का संबंध कुछ ऐसे संगठनों से है जहां सरकारी रुपये का बड़ा ही दुरुपयोग हुआ है। मैं जयप्रकाश बाबू के व्यक्तिगत आचरण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जिस संगठन को सरकारी अनुदान प्राप्त है, उसकी जाँच अवश्य होनी चाहिए।

(माननीय सदस्यों ने सदन में यह कहना एक बार शुरू किया कि इसकी जांच होनी चाहिए।)

श्री अब्दुल गफूर—यह तो बड़ी बात नहीं है। अभी तक तो मैं चरखा संघ और खादी ग्रामोद्योग को एक ही समझ रहा था। वित्त मंत्री के द्वारा यह मालूम हुआ कि ये दो संस्थायें हैं। हमारे यहां आडिटर की अभी कमी है। मैं इसका आडिट करवा दूंगा। (सदन में हल्ला)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है :—

सम्पूर्ण राज्य मंहगाई एवं अभाव से त्राहि-त्राहि कर रहा है जिसका कोई निदान नहीं बताया गया है।

सम्पूर्ण राज्य बेकारी की मार से तबाह और बर्बाद है जिसका कोई निदान नहीं बताया गया है।

राज्य का शासन इतना भ्रष्ट, निहित, स्वार्थ-पक्षी एवं शिथिल है कि उससे कोई भी विकास या जनहित का काम एवं जनसाधारण की जान-माल की रक्षा का काम असंभव हो गया है।

सरकार की नीति और चोरबाजार-पक्षी, जमीन्दार-पक्षी एवं पूंजीवाद-पक्षी है जिससे जन साधारण का जीवन यापन असभव हो गया है।

सरकारी नीति के कारण बिहार राज्य सम्पूर्ण भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में है और जिसे उठाने का कोई समुचित योजना सरकार के सामने नहीं है।

राज्य सरकार ने इस वर्ष को भूमि सुधार वर्ष घोषित किया था जिसे करने में पूर्णतया असफल रही।

बिहार राज्य मुख्यतया हरिजन, आदिवासी एव पिछड़े वर्ग की आबादी का राज्य है जिसके पुनरुत्थान की कोई समुचित योजना नहीं है।

सम्पूर्ण राज्य बिजली, कोयला एवं वैगन संकट से तबाह है जिसके समाधान की कोई चर्चा नहीं है।

सुनिश्चित सिचाई व्यवस्था के अभाव में राज्य की अर्थ व्यवस्था बर्बाद हो गयी है, परन्तु पूर्ण सुनिश्चित सिचाई की कोई कालबद्ध योजना नहीं है।

राज्य सरकार के नये करारोपन यथा पेशाकर, मालगुजारी, बिक्री कर, सिचाई कर, बिजली कर, बस भाड़ा में वृद्धि के कारण सम्पूर्ण राज्य गहरे असंतोष से व्याप्त हो गया है, जिसके निराकरण की कोई योजना नहीं है।'

जो इसके पक्ष में हैं, 'हां' कहें और जो इसके पक्ष में नहीं हैं, 'ना' कहें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—हम ने चैलेंज किया है।

उपाध्यक्ष—इधर हमने नहीं देखा था। हम दुबारा पुट करते हैं।

श्री कमलदेव नारायण सिंह - मेरा प्वायेन्ट आफ ऑर्डर है। परिपाटी

है कि अगर किसी को चैलेंज करना है तो चैलेंज करें, लेकिन जब आपने दो बार कह दिया और चैलेंज नहीं किया गया तब आप दुबारा प्रश्न रखते हैं यह परिपाटी के खिलाफ है।

उपाध्यक्ष—हमने इधर नहीं देखा था ये कहते हैं कि बीच में खड़े होकर बोले थे। हम दुबारा पुट कर देते हैं।

ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह—आप नियम के विरुद्ध कर रहे हैं, इसलिये हम सदन के बाहर जाते हैं। (माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये)

(संशोधन दुबारा पुट किया गया)

(इस अवसर पर घंटी बजी)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

'किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है:—

१. सम्पूर्ण राज्य मंहगाई एवं अभाव से त्राहि-त्राहि कर रहा जिसका कोई निदान नहीं बताया गया है।

२. सम्पूर्ण राज्य बेकारी की मार से तबाह और बर्बाद है जिसका कोई निदान नहीं बताया गया है।

३. राज्य का शासन इतना भ्रष्ट, निहित स्वार्थ-पक्षी एवं शिथिल है कि उससे कोई भी विकास या जनहित का काम एव जन साधारण की जान-माल की रक्षा का काम असम्भव हो गया है।

४. सरकार की नीति चोरबाजार-पक्षी, जमीन्दार-पक्षी एव पूंजीवाद-पक्षी है जिससे जन साधारण का जीवन आपन्न असम्भव हो गया है।

५. सरकारी नीति के कारण बिहार राज्य सम्पूर्ण भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में है, और जिसे उठाने का कोई समुचित योजना सरकार के सामने नहीं है।

६. राज्य सरकार ने इस वर्ष को भूमि सुधार वर्ष घोषित किया था जिसे करने में पूर्णतया असफल रही।

७. बिहार राज्य मुख्यतया हरिजन, आदिवासी एव पिछड़े वर्ग की आबादी का राज्य है जिसके पुनरुत्थान की कोई समुचित योजना नहीं है।

८. सम्पूर्ण राज्य बिजली, कोयला एवं वैगन-संकट से तबाह है जिसके समाधान की कोई चर्चा नहीं है।

९. सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था के अभाव में राज्य की अर्थ-व्यवस्था बर्बाद हो गयी है, परन्तु पूर्ण सुनिश्चित सिंचाई का कोई कालबद्ध योजना नहीं है।

१०. राज्य सरकार के नये करारोपन यथा पेशाकर, मालगुजारी, बिक्री-कर, सिंचाई कर, बिजली कर, बस भाड़ा आदि में वृद्धि के कारण सम्पूर्ण राज्य गहरे, असंतोष से व्याप्त हो गया है, जिसके निराकरण की कोई योजना नहीं है।

तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई :—

हां—३३

श्री अजीजुल हक।
,, तुलसी राम।
,, मोतीलाल सिन्हा कानन।
,, रोशन राम।
,, रामदेव शर्मा।
,, राम स्वरूप सिंह।
,, अनिरुद्ध झा।
,, राम जतन पासवान।
,, विनायक प्रसाद यादव।
,, विन्देश्वरी प्रसाद मंडल।
,, राजकिशोर प्रसाद सिंह।
,, विशेश्वर खां।
,, अम्बिका प्रसाद।
,, प्रभुनारायण राय।
,, लोकनाथ आजाद।
श्रीमती सुनैना शर्मा।
श्री भोला सिंह।
,, रामचन्द्र पासवान।
,, चन्द्रशेखर सिंह।
,, भोला प्रसाद सिंह।
,, चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु।
,, भुवनेश्वर शर्मा।
,, लाल बिहारी प्रसाद।
,, रामाश्रय प्रसाद सिंह।
,, बालिक राम।
,, चतुरानन मिश्र।
श्रीमती शहीदुन्निसा।
श्री चिनमय मुखर्जी।
,, निर्मलेन्दु भट्टाचार्य।
,, शिवकुमार राय।
,, टीकाराम मांझी।
,, केदार दास।
,, रामावतार सिंह।

ना - १३१

श्री हरदेव प्रसाद।
,, नरसिंह बैठा।
,, सीताराम प्रसाद।
,, फैयाजुल आजम।
,, उमेश प्रसाद वर्मा।
,, कृष्ण मोहन पांडे।
,, केदार पांडेय।
,, सगीर अहमद।
,, राजेन्द्र प्रताप सिंह।
,, हफीज ईद्रीस अन्सारी।
,, प्रोफेसर रमाशंकर पाण्डेय।
श्रीमती रामदुलारी सिंह।
श्री नगीना राय।
,, राज मंगल मिश्र।
,, अनन्त प्रसाद सिंह।
,, शंकर नाथ विद्यार्थी।
,, राम नारायण राम।
,, श्रीनिवास नारायण सिंह।
श्रीमती अनुसूया देवी।
,, उमा पांडे।
श्री प्रभुनाथ सिंह।
,, भीष्म प्रसाद यादव।
,, कुमार कालिका सिंह।
,, जनक यादव।
,, रघुनन्दन मांझी।
,, दारोगा प्रसाद राय।
,, भागदेव मिश्र।
,, शमायले नवी।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही।
,, दीप नारायण सिंह।
,, शिव शरण सिंह।
,, शम्भु शरण ठाकुर।
,, राम बाबू सिंह।
,, रघुनाथ झा।
,, सुरेन्द्र राम।
,, राम चरित्र राय यादव।
,, रामफल पासवान।
,, जगन्नाथ मिश्र।
,, विलट पासवान।
,, राधानन्दन झा।
,, बालेश्वर राम।
,, चुल्हाई राम।
,, जगदीश प्रसाद चौधरी।
,, बन्धू महतो।
,, कुम्भ नारायण सरदार।
,, लहटन चौधरी।
,, रमेश झा।
,, विद्याकर कवि।
,, आनन्दी प्रसाद सिंह।
,, जयनारायण मेहता।
,, रसिक लाल रिषिदेव।
,, राम नारायण मंडल।
,, सत्य नारायण यादव।
,, मायानन्द ठाकुर।
,, नजमुद्दीन।
,, महम्मद हुसैन आजाद।

श्री रफीक आलम ।
श्रीमती व्युला दोजा ।
श्री महम्मद अयूब ।
,, विश्वनाथ रिषि ।
,, नथमल डोकानियां ।
,, सैयद मो० जाफर अली ।
, कालीदास मुर्मू ।
, वैद्यनाथ दास ।
,, श्रीकान्त झा
,, पाइका मुरमू ।
,, मदन बेसरा ।
,, सदानन्द सिंह ।
,, मदन प्रसाद सिंह ।
,, रामरक्षा प्रसाद यादव ।
,, ठाकुर कामाख्या प्रसाद सिंह ।
श्रीमती शकुन्तला देवी ।
श्री जयप्रकाश मिश्र ।
,, चन्द्रशेखर सिंह ।
,, रामेश्वर पासवान ।
,, राजो सिंह ।
,, तारणी प्रसाद सिंह ।
,, राजेन्द्र प्रसाद सिंह ।
,, प्रफुल्ल कुमार मिश्र ।
,, घनश्याम सिंह ।
,, मिश्री सदा ।
,, रामदेव राय ।
श्रीमती कृष्णा शाही ।
श्री ठाकुर द्वारिका नाथ सिंह ।
,, रामस्वरूप प्रसाद ।
,, रामराज प्रसाद सिंह ।

श्री नवल किशोर सिंह ।
,, जमील अहमद ।
श्रीमती सुमित्रा देवी ।
श्री सुरजनाथ चौबे ।
,, श्याम नारायण पांडेय ।
,, खालिद अनवर अंसारी ।
श्रीमती मनोरमा पांडे ।
श्री शिवपूजन वर्मा ।
,, जय नारायण ।
,, राजदेव राम ।
,, रामाश्रय प्रसाद सिंह ।
,, रामस्वरूप राम ।
,, नारायण सिंह ।
,, फगुनी राम ।
,, अवधेश्वर राम ।
,, जयराम गिरी ।
,, मोहन राम ।
,, शत्रुघ्न शरण सिंह ।
श्रीमती गायत्री देवी ।
श्री श्यामसुन्दर प्रसाद सिंह ।
,, अमृत प्रसाद ।
,, राजेन्द्र नाथ दां ।
,, पुनीत राय ।
,, तानेश्वर आजाद ।
,, मुरली भगत ।
,, विन्देश्वरी दूबे ।
,, नन्दकिशोर सिंह ।
,, विरेन्द्र कुमार पांडेय ।
,, दुर्गाचरण दास ।
,, शंकर दयाल सिंह ।

श्री शिवुरंजन खां।
,, सनातन मांझी।
,, सिदुक हेमरम।
,, वनमाली सिंह मुण्डा।
,, राम रतन राम।
,, उमरांव साधो कुजुर।
,, देवदत्त साहु।
,, एस० के० बागे।
श्री साइमन तिग्गा।
,, बैरागी उरांव।
,, श्रीकृष्ण भगत।
,, विजय विरेन्द्र कुमार।
,, भालदेव राम।
,, भीष्म नारायण सिंह।
,, रामदेनी राम।

उपाध्यक्ष—मतदान का फल इस प्रकार है :—

पक्ष में—३३
विपक्ष में—१३१

सशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायँ—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है—

(क) बिहार राज्य सरकार मंहगाई, बेकारी तथा भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ रही है।

(ख) खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के चलते जनता को अपार कष्ट हो रहा है।

(ग) गेंहूँ तथा कोयले के राष्ट्रीयकरण तथा लेभी का गलत प्रयोग के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा अभाव पैदा हो गया है।

(घ) इस घोर संकट के समय राज्य सरकार अनावश्यक खर्चे तथा करों का भार गरीब जनता पर लाद रही है।

(ङ) प्रति वर्ष शिक्षित तथा अशिक्षित बेकार लोगों की संख्या बढ़ रही है तथा सरकार न तो पूर्णतः रोजगार का और न बेकारी भत्ता देने का प्रबंध कर रही है।

(च) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में न तो सुधार लाया जा रहा है और न रोजगार-प्रदत्त शिक्षा दी जा रही है।

(छ) कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है।

(ज) सिंचाई तथा बिजली पर विशेष ध्यान न देकर खेती तथा छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देने में सरकार असमर्थ रही है।

(झ) राज्य सरकार बाणसागर सिंचाई योजना तथा कटिहार थर्मल पावर स्टेशन की योजना को बिहार के हित में कार्यान्वित करने में असमर्थ रही है।

(ट) केन्द्र सरकार से पर्याप्त साधन तथा खाद्यान्न प्राप्ति करने में असफल रही है।

(ठ) युवकों तथा छात्रों की मांगों को अनसुनी कर उनके आंदोलन को दमन करने में ज्यादती की गयी है।

(ट) प्रशासन के सभी लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में यह सरकार अक्षम है।

संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं।

श्री भोला प्रसाद सिंह—इस पर वोटिंग कराया जाय।

उपाध्यक्ष—लेकिन मूल प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कभी हुआ है। इस तरह की परम्परा नहीं है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—मैं मानता हूँ कि परम्परा नहीं है, लेकिन राज्य की जो स्थिति है उसमें वोटिंग होना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष—संशोधन के प्रस्ताव पर डिविजन हुआ है, लेकिन मूल प्रस्ताव पर डिविजन अभी तक नहीं हुआ है।

(इस अवसर पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस (संगठन) वाकआउट कर गये)

श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—नियम में कहीं ऐसी बात नहीं है कि मूल प्रस्ताव पर डिविजन नहीं हो।

उपाध्यक्ष—मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो वोटिंग करवा देंगे।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "सदस्यगण इस अभिभाषण के लिये राज्यपाल के कृतज्ञ हैं।"

(खड़े होकर मतदान हुआ।)

उपाध्यक्ष—मतदान का फल निम्न प्रकार है—

पक्ष में— १२१

विपक्ष में— ८

धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

फुलेना राय की गिरफ्तारी की सूचना

उपाध्यक्ष मुझे सविनय सूचित करना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा १२० बी०/३०७।३२४।३४ तथा २५-ए २६।२७ आर्म्स एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत कोतवाली थाना मुकदमा संख्या १७ (६) ७४ के अभियुक्त श्री फूलेना राय, सदस्य, बिहार विधान-सभा ने आज दिनांक ११ जून, १९७४ के ३ बजे अपराह्न में मेरे समक्ष आत्म-समर्पण किया। उन्हें आरा मंडल कारा हिरासत में रखा गया है।

निवेदन के सम्बन्ध में सूचना

उपाध्यक्ष—एक निवेदन है सदन की राय हो तो मैं इसे विभाग में भेज दूँ।

(बैठे-बैठे सभी सदस्य 'इसे विभाग में भेज दिया जाय')।

इसे उचित कारवाई हेतु सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जायगा।

सभा बुधवार, तिथि १२ जून, १९७४ के ११ बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गयी।

विश्वनाथ मिश्र
सचिव
बिहार विधान-सभा

पटना :
तिथि ११ जून, १९७४